Haryana Vidhan Sabha

Debates

16th June, 1967

Vol. I – No. 18

Official Report

Contents

Friday, the 16th June, 1967

	Pages
Starred Question and Answers	(18)1-27
Unstarred Question and Answer	(18)27
Call Attention Notice	(18)28
General Discussion on the Budget (Resumption)	(18)28
Extension of Time of the Sitting	(18)57
General Discussion on the Budget (Resumption) (concld)	(18)57-62

HARYANA VIDHAN SABHA

Friday, 16th June, 1967

The Vidhan Sabha met in the Hall of Haryana Vidhan Sabha, Vidhan Bhavan, Chandigarh, at 8 a.m. of the Clock. Mr. Speaker (Chaudhri Sri Chand) in the Chair.

STARRED QUESTIONS AND ANSWERS

Transfer of Government Employees

Shri Daya Krishan: Will the Chief Minister be pleased to state whether any rules or regulations/instructions are followed by Government while transferring Government servants from one place to another, if so, the details there of?

Rao Birendra Singh: Government have issued instructions regarding the transfer of Government employees which lay down that ordinarily efforts should be made to keep an officer/official at a job for at least 3 years unless an earlier transfer becomes necessary because of the needs of the publiuc service or because of extraordinary circumstances. It has also been laid down that normally transfers should not take place in the months other than March or April so that children's education does not suffer. Efforts are also made to post husbands and wives in Government service at the same station.

श्री दया कृष्ण: क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि सिफारिश की बिना पर कितनी ट्रांस्फर्ज होती है।

मुख्य मंत्रीः कोई भी नहीं होती।

श्री दया कृष्णः क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएगें कि जो हस्बैंड्ज और वाईवज मुख्तलिफ स्टेशनों पर सर्विस कर रहे हैं क्या उन को इकट्ठा किया जाएगा ?

मुख्य मंत्रीः आप अगर सिफारिश करेंगे तो कर देंगे।

श्री दया कृष्णः आप ने तो फरमाया था कि सिफारिश आप मानते नहीं।

श्री रण सिंहः क्या कुछ ऐसे केसिज भी हैं जो तीन साल से कम अर्से में ही ट्रांसफर किए गए हों। कुछ अफसर चण्डीगढ़ से भी तीन साल से पहले फील्ड में ट्रांस्फर किए गए हैं। उस का क्या कारण है?

मुख्य मंत्रीः कोई खास केस बतांए तो मैं पता कर सकता हूं। जनरल तौर पर कैसे बता सकता हूं।

चौधरी रिजक रामः क्या मुख्य मंत्री साहिब बताएंगे कि जो लेडी मेंम्बर्ज हैं उनके हस्बेंडज को भी एक जगह पर उनके साथ रखा जाएगा?

मुख्य मंत्रीः आप कोई खास केस बताएं।

चौधरी रिजक रामः श्रीमती प्रसन्नी देवी है। उनका husband was teaching at Rohtak for the last so many years लेकिन अब उन को ट्रांसफर करके नारनौल भेजा गया हैं।

मुख्य मंत्रीः लेडी मेम्बर को अपरे हस्बैन्ड के साथ रहना चाहिए।

चौधरी रिजक रामः मैने चीफ मिनिस्टर साहिब को खास केस बताया है, लेकिन उन्होने ऐसे ही टाल दिया है। जब सरकारी मुलाजमों को ऐसी फैसिलिटी दी जाती है तो मेम्बरो को भी वह फैसिलिटी देनी चाहिए। स्पीकर साहिब, आप को भी अपने गुड आफिस को इस काम के लिए यूज करना चाहिए।

श्री अध्यक्षः वह पोस्ट तो रोहतक में रही ही नहीं।

चौधरी नसीब सिंहः दूर दूर रहने से फैमिली प्लैनिंग होती रहती है।

श्रीमती प्रसन्नी देवीः हम ने तो पहले ही फैमिली प्लैनिंग की हुई है। आप फिक्रन करें।

Distribution of Sugar in the State

***254. Smt. Om Prabha Jain:** Will the Chief Minister be pleased to state:-

a) The quantity of sugar which was available with the Government during the months of November, December, 1966 and January and February, 1967, together with the mode and the quantity thereof distributed per head/per family in the rural and urban areas, separately;

b) The present position of sugar and the quantity thereof permissible pe head in rural and urban areas, separately?

Major Amir Singh (State Minister for Rural Electrification): (a) and (b) A statement containing the required information is laid on the Table of the House.

Statement

(a) All location of sugar received from the Government of India	Quantity in tones
November, 1966	6560
December, 1966	6560
January, 1967	5000
February, 1967	5000

MODE OF DISTRIBUTION

i. In urban areas through fair price depots.

ii. In rural areas through o-operative Societies.

QUANTUM OF ISSUE

Name of Month	Urban Areas	Rural Areas
From November, 1967 to January, 1967	One kilogram per head normal quota plus two kilograms per head as adhoc additional quota	Up to three kilograms per head (According to individual requirements as verified by Panchayats)
February, 1967	One kilograms per head normal quota plus one kilogram per head as adhoc additional quota	Up to tow kilograms (According to individual requirements as verified by Panchayats)

(b) Month wise allocation received from the Government of India	Quantity in tones
April, 1967	3600
May, 1967	3008
June, 1967	Allocation will be received from Government of India after 15th June

QUANTUM OF ISSUE

Name of Month	Urban Areas	Rural Areas
May, 1967	800 grams per head	100 grams per head while the remaining quota of consumers was diverted for marriages in rural areas.
June, 1967	800 grams per head	This month being the peak period for marriages in rural areas, the entire quota of consumers ha been diverted for issue on marriages in the rural areas for meeting increased demand of sugar for the purpose.

श्रीमति ओम प्रभा जैनः आपने बताया है कि जनवरी, फरवरी में पांच हजार टन चीनी का कोटा था और अब 3008 टन है, जनवरी–फरवरी मं तो शहरों और देहातों मैं दो–दो किलो चीनी दी जाती थी। लेकिन अब सिर्फ 2 हजार टन कोटा कम हुआ है लेकिन उस के हिसाब से लोगों के चीनी के राशन की मिकदार जो कम की गई है वह बहुत ज्यादा है। इस की क्या वजह है।

राज्य मंत्रीः आप हम को समझा दें कैसे बढ़ा सकते हैं तो हम गौर कर लेंगे।

श्री भगवान देव प्रभाकरः क्या यह ठीक है कि जो कोटा शहारों का है वह भी पूरा नहीं मिला है और उससे कम मिला है ?

राज्य मंत्रीः अगर ऐसी कोई बात है और नोटिस में लाएंगे तो जांच करेंगे।

श्री भगवान देव प्रभाकरः जो सिस्टम देहात में चीनी बाटने का बनाया गया है उस में पटवारियों और सरपंचों को अटैस्ट करने का अधिकार दिया गया है, जिस से हेरा फेरा हो रही है। क्या इस सिस्टम को बदलने का सरकार विचार कर रही है ?

राज्य मंत्रीः इसके लिए सैपेरेट नोटिस दें।

श्री हीरा चन्दः चीनी की बांट में देहात और शहरों में जो भेदभाव की नीति चल रही है वह कब तक चलेगी ?

राज्य मंत्रीः यह नीति कांग्रेस वालों की चलाई हुई है इसका मैं क्या जवाब दूं।

श्रीमति ओम प्रभा जैनः क्या यह आपके नोटिस में है कि शादियों के लिए गलत सर्टीफिकेट दे कर चीनी दी गई है और वह ब्लैक में बिक रही है ?

राज्य मंत्रीः मेरे नोटिस में ऐसी बात नहीं आई है अगर आप लाएंगे तो जांच की जाएगी।

चौधरी रिजक रामः जहां तक इन्टरनल डिस्ट्रीब्यूशन का सवाल है कि शहर और देहता में कितनी कितनी होनी चाहिए स्टेट गवर्नमैंट के अधिकार में है या सैंटर के अधिकार में है ?

राज्य मंत्रीः यह आपकी ही सरकार की कृपा थी कि एक ग्राम का भी गांव वालों को अधिकार नहीं था जो बचती थी वही देते थे लेकिन हमारी सरकार ने इस असूल को नहीं माना और हमने सौ ग्राम पर हैड कोटा गांव वालों के लिए मुकर्रर कर दिया। जैस जैसे सप्लाई बढ़ती जाएगी हमारी कोशिश होगी कि सब को बराबर दी जाए।

चौधरी रिजक रामः क्या सौ ग्राम का मतलब है कि डेढ़ छटांक पर हैड का कोटा आप देहात वालों को दे रहे हैं ?

मुख्य मंत्रीः जी हां। वैसे 175 ग्राम है लेकिन 75 ग्राम मई–जून में शादियों के लिए डाइवर्ट कर दिया गया है।

चौधरी शिव राम वर्माः क्या यह ठीक है ि कवह सौ ग्राम भी नहीं दी जा रही है। शहरों के बराबर लाने में कितना वक्त लगेगा ?

मुख्य मंत्रीः अभी कोटा जमा कर रहे हैं।

श्री रणधीर सिंहः जो शूगर मिल एरियाज हैं वहां पिदले तीन महीने से चीनी नहीं दी गई है। क्या वहां देना जानबूझ कर बन्द किया हुआ है ?

राज्य मंत्रीः हम शूगर मिल एरिया और दूसरे एरिया में फर्क नहीं करते हैं।

श्रीमति ओम प्रभा जैनः क्या यह आपके नोटिस में है कि चीनी चार रूपए फी किलो ब्लैक में बिक रही है ?

राज्य मंत्रीः सरकार के नोटिस में ऐसी कोई ात नहीं है अगर कोई केस बताएंगे तो देख लेना एक घंटा के अन्दर अन्दर राऊंड अप कर देंगे।

चौधरी रिजक रामः यह जो आपने सौ ग्राम का कोटा किया है किस महने से किया है और क्या इसकी डिस्ट्रीब्यूशन हुई है या यह फैसला कागजात में ही है ?

राज्य मंत्रीः यह मई के महीने में दिया गया था। और डिस्ट्रीब्यूशन हुई लेकिन कुछ जिलों में जहां शादियों की तादाद ज्यादा हो गई डी.सीज ने इस कोटा का कुद हिस्सा या सारे का सारा उधर डाइवर्ट कर दिया।

चौधरी रिजक रामः क्या इस शारटेज के पेशेनजर सरकार ने यू.पी. से खांडसारी हासिल की है ?

मुख्य मंत्रीः मैंने एक चिट्ठी चोधरी चरण सिंह को लिखी थी कि हमें खांडसारी इम्पोर्ट करने की इजाजत दी जाए लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया।

श्री भगवान देव प्रभाकरः क्या यह आपके इल्म में है कि जहां ऐस.डी.ओ. ने और सिविल सप्लाई वालों ने शादियों के लिए परमिट दिए थे उनके लिए भी कोटा नहीं मिला और परमिट पड़े रहे ?

राज्य मंत्रीः मेरे नोटिस में नहीं है अगर लाएंगे तो जांच करेंगे।

श्री रणधीरः शूगर मिल एरिया में चीनी देना बहुत जरूरी है क्योंकि उन से जबरदस्ती गनना लिया जाता है ?

श्री अध्यक्षः यह सवाल नहीं है।

श्री दीन मुहम्मदः क्या यह ठीक है कि शादियों के नाम पर बोगस परमिट दिए गए और वह चीनी ब्लैक में बिक रही है। क्या इसकी इनक्वायरी करेंगे ?

राज्य मंत्रीः ऐसे केस नोटिस में लायेंगे तो उनके खिलाफ इनक्वायरी करेंगे।

श्री दया कृष्णः क्या यह आप के इल्म में है कि कुआप्रेटिव सुसाइटीज ने बांटने का काम ठीक नहीं किया और शादियों के दिनों में चीनी नहीं दी गई ? इसके बारे में क्या इन्तजाम कर रहे हैं ?

राज्य मंत्रीः मेरे नोटिस में कोई केस लायेंगे तो पता करके कार्यवाही की जाएगी।

श्री दया कृष्ण: क्या यह उनके नोटिस में है कि जिला जींद में शादियों के दिनों में चीनी नहीं मिली और बिल्टी जो बाहर से आई थी वह जान बूझ कर गुम कर दी गई ?

राज्य मंत्री: आप इतने दिनों से यहां है कभी आपने बताया नहीं अगर बताते तो ऐक्शन लेते। अब भी बताएंगे तो एक्शन लेंगे ?

श्री ओम प्रकाश शर्मा: यह जो हर रोज वजीरों की कोठियों पर स्वीट डिश पार्टियां होती हैं क्या उनके लिए कोई कोटा अलैहदा मिलता है ? (हंसी)

Starred Question No. 297

Mr. Speaker: Extension has been asked for in respect of Starred Question No. 297. It is, therefore, postponed.

Districts in the Haryana State

***245. Ch. Rizaq Ram:** Will the Minister for Revenue be pleased to state the number of districts in the Haryana State together with their (i) names (ii) area in square miles and population of each separately?

Sh. Chand Ram (Deputy Chief Minister):

Name of the District (i)	Area in sq. Kilometers (ii) (a)	Population (ii) (b)
Hisar	13890	1540568
Rohtak	6040	1420391
Gurgaon	6086	1240706
Karnal	7964	1490430
Ambala	3702	885785
Jind	2712	464873
Mahendergarh	3475	547850

चौधरी रिजक रामः यह जो आपने जिलों की पापुलेशन और एरिया की फिगर्ज दी हैं इस में बड़ी डिसपैरिटी है क्या इसके पेशेनजर इन जिलों की रीआर्गेनाईजेशन के बारे में कोई प्रोजोजल सोच रहे हैं ?

उप–मुख्य मंत्रीः इस बारे में पंजाब मैं एक कमेटी बनाई गई थी और कुछ की रिक्मैंडेशन्ज थीं और उसका फैसला उस वक्त हो गया था। यह जो डिसपैरिटी आप ने बताई है इसके बारे में अभी कोई बात विचार में नहीं है और न विचार हुआ है। हां यह सोचने वाली बात जरूर है।

श्रीमति ओम प्रभा जैनः जैसा उन्होंने कहा कि विचार की बात है तो क्या एम.एल.एज. की राये लेंगे और क्या वहां के सारे फैक्ट्स ऐंड फिगर्ज इकट्ठे करके फैसला करेंगे ?

उप–मुख्य मंत्रीः यह तो एडमिनिस्ट्रेटिव चीज है। इसके अन्दर आप लोगों की राय लेने के बाद जैसा मुनासिब समझा जाएगा वैसा किया जायेगा।

चौधरी रिजक रामः अभी मिनिस्टर साहिब ने फर्माया है कि अर्सटवाइल पंजाब स्टेट में एक कमेटी मुकर्रर की गई थी, जिसने कुछ रिक्न्मैंडेशन्ज की थीं और जिन में से कुछ मान ली गई थीं और कुछ बाकी रहती हैं। तो क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे िकइस तरह की कमेटी यहां भी सैट अप की जायेगी ?

उप–मुख्य मंत्रीः अभी कैबिनेट ने इस तरह की बात पर विचार नहीं किया है।

श्रीमति ओम प्रभा जैनः सभी मिनिस्टर साहिब ने फरमाया कि इसके लिए कोई प्रोजाजल नहीं है। तो क्या वे बतायेंगे कि जब कभी प्रोपोजल होगी तो पब्लिक से और एम.ऐल. एज. से डिसकस किया जाएगा ?

उप–मुख्य मंत्रीः मैं इस मामले में अभी कमिट नहीं करता क्योंकि अभी सोचा ही नहीं गया है।

चौधरी रिजक राम: गवर्नमैंट कुछ इकोनोमी मेयर्ज उठा रही है। तो मैं मिनिस्टर साहिब से पूछना चाहता हूं कि यदि यह कर दिया जाये तो क्या यह इकानोमी की तरफ एक कदम नहीं होगा ?

उप–मुख्य मंत्री: मैंने अर्ज किया कि सारे आस्पैकट्स पर विचार किया जाएगा यह इकानोमी वाली बात भी देखी जायेंगी और सब बातों पर विचार करने के बाद जो ठीक होगा वह किया जाएगा।

Income from the agricultural farms, in Hisar District

***201. Sh. Bhagwan Dev Parbhakar:** Will the Minister for Revenue be pleased to state:-

a) The number and names of the Government Agricultural Farms in Hisar District and the amount of income derived there from during the last three years.

b) The details of the production of wheat, gram and sugarcane at each of the said farms during the said period together with the yield per acre, commodity-wise?

Sh. Chand Ram (Deputy Chief Minister): Parts (a) & (b): A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Sr.	Name of the Seed Farm	Income		
		1963-64	1964-65	1965-66
		Rs.	Rs.	Rs.
1	Seed Farm, Hisar	28137.29	31864.23	21067.47
2	Seed Farm, Hansi	12679.28	8888.84	16098.40
3	Seed Farm, Barwala	6200.17	3740.44	6645.93
4	Fatehabad	2049.00	1737.00	1655.16
5	Bahuna	2817.00	3673.00	Not intimated
6	Natar	2237.00	1492.00	1329.49
7	Akkanwali	3751.00	3562.00	3104.98
8	Mangiana	6824.00	10408.00	16235.61
9	Sirsa	31996.00	38441.00	22218.00

Statement

Sr.	**Name of Paper/periodical**	**Place/Tehsil from where published**	**Amount**
1	**2**	**3**	**4**
II – Papers/Periodical published outside the State			**Rs.**
	(a) English		
1	Indian Express	Delhi	11650.90
2	Patriot	Delhi	4068.80
3	Hindustan Times	Delhi	5488.71
4	Times of India	Delhi	2816.00
5	Hindu	Madras	338.80
6	Indian Express	Bombay	317.62
7	Amrit Bazar Patrika	Calcutta	488.40
8	Caravan	Delhi	264.00
9	Link	Delhi	701.50
10	National Star	Delhi	228.15
11	National Solidarity	Delhi	209.44
12	Rajasthan Public	Jaipur	250.00

	Relations Assn.		
13	Seventh All India Children Conf.	Delhi	250.00
14	Guru Gobind Singh Foundation	Chandigarh	500.00
15	Eastern Economist	Delhi	175.00
16	Statesman	Delhi	422.40
17	Punjab Sentinel	Chandigarh	122.40
18	Socialist Congressman	Delhi	360.00
19	All India Congress Committee	Delhi	200.00
20	INTUC	Delhi	400.00
21	Haryana United Nations Asson.	Rohtak	220.00
22	All India Small and Medium Newspaper Editors Association	Kanpur	200.00
23	Indian News and Feature Alliance	Delhi	300.00
24	Shankar Weekly	Delhi	345.58
(b) Hindi			

1	Milap	Jullundur	2018.16
2	Nav Bharat Times	Delhi	2147.20
3	Vir Arjun	Delhi	2059.20
4	Hindustan	Delhi	4604.00
5	Jagrat Haryana	Delhi	74.36
6	Hindi Times	Delhi	724.58
7	Punjab Kesri	Jullundur	996.30
8	Sewagram	Delhi	687.28
(c) Urdu			
1	Milap	Jullundur	2113.32
2	Partap	Delhi	3053.56
3	Tej	Delhi	1783.02
4	Savera	Delhi	917.28
5	Hind Samachar	Jullundur	1087.48
6	Jagat	Delhi	18.48
7	Parbhat	Jullundur	35.90
8	Partap	Jullundur	628.60
9	Pardeep	Jullundur	495.00
10	Rohjan	Ludhiana	60.50

11	Hindu	Jullundur	210.10
12	Atalique	Delhi	47.85
13	Lalkar	Delhi	95.70
14	Bhartiya Spoot	Delhi	60.50
15	Punjab Congress Patrika	Chandigarh	102.30
16	Jan Nissar	Delhi	127.50
17	Missihi Duniya	Delhi	46.75
18	Biswin Sadi	Delhi	170.00
19	Motor Transport Gazette	Chandigarh	224.00
20	Driver	Jullundur	280.00
21	Transport Worker	Delhi	60.00
22	Transport Gazette	Delhi	240.00
23	Motor Transport Worker	Jullundur	40.00
(d) Punjabi			
1	Ajit	Jullundur	733.60
2	Ranjit	Patiala	233.64
3	Nawan Hindustan	Delhi	641.24

4	Mel Milap	Chandigarh	289.41
5	Akali Patrika	Jullundur	750.20
6	Nawan Zamana	Jullundur	182.79
7	Lok Darshan	Delhi	119.16
8	Parkash	Chandigarh	189.69
9	Sikh	Amritsar	60.50
10	Fateh	Delhi	46.20
11	Ranjit Nagara	Chandigarh	60.50
12	Panth Parkash	Delhi	123.20
13	Mauji	Jullundur	84.80
		Total	**92102.98**

श्री भगवान देव प्रभाकर: क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कांग्रेस के शासन में प्लैन्ज के बारे में जो पक्षपात से काम लिया गया है, वह पक्षपात अब दूर किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष: कवैस्चन ओवर हो गया।

मैं हाउस की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि जिन सवालों के जवाब नहीं आये हैं उनके लिये मिनिस्टर साहिबान मण्डे को प्रिपेयर होकर आयेंगे।

UNSTARRED QUESTION AND ANSWERE

National Defence Fund Collected by the Kurukshetra University

***23. Sh. Om Parkash:** Will the Minister for Education be pleased to state the amount of National Defence Fund collected by the Kurukshetra University together with the amount left after bearing of the expenses of the Kurukshetra University Canteen for Jawans and also the date when the remaining amount was deposited by the University with the National Defence Fund authorities?

Sh. Hardwair Lal:	**Rs.**
Receipt during 1965-66	6449.90
Expenditure during 1965-66	5402.46
(For running Canteen for Jawans)	401.46

Presented to Chief Minister, Punjab	5001.00
Receipt during 1966-67	26.00
Expenditure during 1966-67	Nil

The balance amounting to Rs. 1073.44 lying with the University has been remitted to the National Defence Fund on 8th June, 1967.

CALL ATTENTION NOTICE

Sh. Daya Krishan: My call Attention notice regarding hunger-strike by public servants stands admitted by you but so far no statement thereon has been made by the Government. Would you kindly request the Government to make a statement about it?

श्री अध्यक्षः हां जी, मुख्य मंत्री साहिब को चाहएि था इस का जवाब दे देते।

मुख्य मंत्रीः स्पीकर साहिब, अभी तो कोई भूखहड़ताल हुई नहीं, न ही कोई मरा है। श्री दया कृष्ण जी खाना ले कर जाते हैं, उनके लिये। जब कोई बात होगी तो सोचेंगे।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET (Resumption)

श्री गणपत (एस.सी., दादरी): स्पीकर साहिब, बजट पर कुछ कहने से पहले मैं प्रैस की मारफत हाउस को बताना चाहता

हूं कि मरा संकट दल से कोई सम्बन्ध नहीं है और मैं कांग्रेस पार्टी में हूं।

Development Minister: On a point of order, Sir. Can any member address Press persons from the floor of the House? He cannot do so. In the House he can address the Speaker and none else.

Mr. Speaker: This is not relevant. I would request the Hon. Member to speak on the Budget.

श्री गणपत रायः स्पीकर साहिब, बजट में हरिजनों के लिये 70 लाख रूपया रखा गया है जो कि मैं समझता हूं बहुत कम है। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार की मजबूरियां होती हैं, इसलिये यह अधिक धन राशि नहीं दे सकी। लेकिन कुछ और ऐसे तरीके हैं जिन कोअगर अपनाया जाये तो सरकार के पास काफी पैसा आ सकता है और हरिजनों का अगर सरकार कल्याण करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन आज हम देख रहें हैं कि हरिजनों की बुरी तरह से एक्सप्लाएटेशन हो रही है। आज हरिजन बर्ग तथा मजदूर वर्ग जो नहरों, सड़कों तथा दूसरे पुलों वगैरा पर काम करते हैं उन की भलाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर सरकार उस तरफ ध्यान दे तो उनकी हालत सुधर सकती हैं।

मुख्य मंत्रीः इधर आ कर ध्यान करने लग जाओ तब सुधर जाएगी।

श्री गणपत रायः स्पीकर साहिब, आज नहरों पर, भट्टों पर जो ठेकेदार हैं, वह मजदूरों की मेहनत से अपनी झोलियां भर रहे हैं। आज मजदूरों की वर्किंग कंडीशन्ज बहुत खराब हो चुकी है और जो 1947 से पहले उनके वेतन थे वही वेतन उन्हें आज भी मिल रहे हैं। अगर सरकार ईमानदारी से कोशिश करे तो बिना जनता पर बोझ डाले उन की हालत को सुधार सकती है। दूसरा मसला हरिजनों को सरप्लस जमीनें देने का है। आज यह उनके लिए स्वपन बर कर रह गया है कि उन को कभी जमीनें मिलेंगी। हरिजनों को जमीनें दिलाने के लिए सरप्लस लैंड का कानून तो बना लेकिन उस के साथ ही अमैंडमैंट ला कर एक हाथ से जो चीज दी थी वह दूसरे हाथ से छीन ली ई और सरप्लस जमीन का मसला एक धोका बन कर रहा गया और जो बड़े जमींदार थे जिन के पास हजारों एकड़ जमीन थी आज वह उन्हीं के पास बनी है। इसी तरह नजूल जमीन और पंचायतों की जमीनों में भी धांधली मची हुई है। इवैक्वी लैंड का जहां तक ताल्लुक है उसकी आक्शन हुई थी। .....

Mr. Speaker: No interruption please.

श्री गणपत रायः स्पीकर साहिब, बहुत से ऐसे केसिज हैं, हरिजनों ने नीलामी में जमीनें लीं लेकिन 3/4 सालों से उन्हें पोजैशन नहीं मिल रहा और नायब तहसीलदार हरिजनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत से खेतों के उन को गलत नम्बर दे दिए गए जिस की वजह से उन्हें पोजैशन नहीं मिल रहा है। अगर

हमारी सरकार और उनके अफसर नेकनीयती से काम करें तो उन की ऐसी तकलीफें दूर हो सकती हैं।

इस बजट स्पीच में छुआ छूत दूर करने का जिक्र किया गया है। आज हमें आजादी मिले को 20 साल हो गये हैं लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी छुआ छूत उसी तरह से चल रही है। आज एक हरिजन गांव के कामन कुएं से पानी नहीं ले सकता। मैं निवेदन करूंगा कि अगर हालात ठीक न किए गए तो बहुत मुशिकल हो जायेगी।

छूआछूत का जहां तक हाल है कि स्कूलों में हरिजनों को चपड़ासी तक नहीं रखा जाता है क्योंकि हैडमास्टर समझतें हैं कि अगर इनको रखेंगे तो इनके हाथ से पीने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हरिजनों के साथ आजादी के बाद भी यही सलूक होता रहा तो इस आजादी का उनको क्या फायदा है ?

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

हरिजन स्टूडैंट्स को जो वजीफें दिए जाते हैं उन में बड़ी धांधली चलती है। सारा साल गुजर जाता है लेकिन वजीफा नहीं मिलता है। इसके इलावा मंहगाई इतनी हो गई है लेकिन वजीफों को शरह वही है जो 1947 में फिक्स की गई थी। इस रकम से गुजारा नहीं होता है इस लिए इस शरह में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी तरह हरिजन स्टूडैंट्स को जो करजे दिए जाते हैं उस में भी बुरा हाल हैं। सैशन के शुरू से ही इतनी दरखासतें

ऐजुकेशन डिपार्टमैंट को आई हुई हैं लेकिन कोई गौर नहीं किया जाता है। फिर हरिजन वैलफेयर डिपार्टमैंट में जो धांधली चल रही है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं अर्ज करता हूं कि जो हरिजनों की दशा सुधारने के ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी दशा सुधारने का बड़ा दावा करते हैं और पिछले बोस साल से यह ठेकेदार आपने हाथ में रखे हुए हैं अगर इस सरकार में हिम्मत है तो मेरी दरखासत है कि हरिजन वैलफेयर डिपार्टमैंट उस ठेकेदार मिनिस्टर से ले लें और दौलता साहिब को दे दें या और दूसरे मिनिस्टर को दे दें लेकिन यह बीमारी जिन्होंने बढ़ाई है उन से यह महकमा ले लें।

चौधरी नसीब सिंह (कलानौर): डिप्टी स्पीकर साहिब, आज इस बजट पर बहस का तीसरा दिन चल रहा है और इस पर काफी बहस हो चुकी है। इस बजट को कई किस्म के नामों से पुकारा गया है लेकिन बाहर जब प्राइवेट तौर पर बात होती है तो आपोजीशन वालों को भी यह कहते सुना है कि बजट तो अच्दा बना है मगर मुखालफत तो करनी ही है। मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि आप मुखालफत के लिए मुखालफत बेशक कर लें लेकिन पिछली सरकारों के बीस सालों के बजटों से अब मुकाबला करते हैं तो पता लगता है कि यह बजट सही मायनों में अकालियों में दब कर रहने वाली इस बंटवारे में हरियाणा से बेइन्साफी कराने वाली और बीस साल तक गलत नीतियों पर चलने वाली कांग्रेस सरकार के बजटों से अच्छा है और इस छोटे से उजड़े प्रांत की

गरीब जनता की आशाओं का आइना है और बड़ी दूर देशों से तैयार किया गया है। इस बजट में तमाम पहलुओं को जरूरत के मुताबिक और योजना के अनुसार कबर किया गया है। इसलिए यह अब तक के बजटों में से सबसे अच्छा है। कुछ टैक्सों के बारे में आपोजीशन की तरफ से वावेला किया गया है। इस में शक नहीं कि हरियाणा की जनता जो काफी दिनों से पिस रही थी और टैक्स ही टैक्स दे रही थी जिसके बदले उसे कुछ मिल नहीं रहा था उसकी बढ़त ज्यादा इच्छा और भावना इन टैक्सों से बचने की थी और वह समझती थी जब हरियाणा बनेगा तो इस कमर तोड़ टैक्सों से उसे राहत मिलेगी। कोई सूझबूझ रखने वाला आदमी समझ सकता है कि यह टैक्स ही हरियाणा की पैदायश के साथ पैदा हुए हैं। इतना छोटा सा सूबा जिसके अन्दर पिछले बीस साल में कोई डिवैलपमैंट नहीं हुई, आमदनी का कोई जरिया नहीं पैदा किया गया और न पैदा होने दिया गया। वह किस तरह बगैर टैक्सों के चल सकेगा, यह बात सभी जानते थे कुछ दूरअंदेश आदमी इसी डर से पंजाबी सूबा बनाने की मुखालिफत भी करते थे क्योंकि हरियाणा का जो इलाका रह जाएगा वह समझते थें कि वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुशकिल में पड़ जाएगा और जनता पर भारी टैक्स लगाने पडेंगे। इसलिए अब टैक्सों की मुखालिफत करना और उन से डरना समझ में आने वाली बात नहीं। पिछली सरकार ने जनता की तकलीफों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और वह तो इस बात की आदी थी कि जनता रोती रहे और वह अपनी चाल चलते रहें लेकिन जो नई सरकार बनी है

इसे जनता की तकलीफों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि आज हरियाणा में रैवोलूशन हुई है और जनता में जो जोश पैदा हुआ है कि हम अपने सूबे की तरक्की करेंगे और देश की दूसरी स्टेट्स के बराबर दरजा हासिल करेंगे वह जोश हमने कायम रखना है और इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुरबानी करनी पड़ेगी, बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ेगा और हम सारे लैजिस्लेटर्ज को सारे प्रदेश के लिए एक हो कर काम करना पड़ेगा और हम सारे लैजिस्लेटर्ज को सारे प्रदेश के लिए एक हो कर काम करना पड़ेगा वरना यह हमारा अपना अपना सवाल कि मेरी हकूमत बनी है तो यह अब क्यों छिन जाए और अब मेरी ही बनी रहे अगर इनहीं झगड़ों में और जोड़ तोड़ में हम लगे रहे तो हमरार प्रदेश तकरक्की नहीं कर सकेगा, तरक्की के साधन नहीं जुटाए जा सकेंगे और इस प्रदेश की जिन्दगी और इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आज इस बात की सख्त जरूरत है कि हमें सारे ही लैजिस्लेटर्ज को एक हा कर इस प्रदेश के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि यह जो टैक्स लगे हैं इनके बारे में सोचना है कि क्या यह हमारे प्रदेश की तरक्की के लिए जरूरी है या नहीं। सरकार ने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए आब्याना टैक्स है और कुरूक्षेत्रयूनिवर्सिटी की लिए जो मालगुजारी बढ़ाई है चाहे एक साल के लिए बढ़ाई है उसे भी जनता बोझ समझती है। एक साल के लिए तो जनता बोझ उठाने के लिए तैयार है लेकिन डर इस बात का है कि कहीं पिछली सरकार की पैरवी करते हुए यह टैक्स

पक्का ही न हो जाए जिस तरह वह एक साल का बहाना लगाकर बाद में टैक्स पक्का कर देती थी। इस लिए जनता आशा करती है कि यह सरकार अपने वायदे के अनुसार अगले साल यह टैक्स हटा लेगी। जनता सरकार ये यह भी आशा करती है कि इन टैक्सों से लिया एक एक पेसा वह बचाएगी और उसका बोझ कम करने की कोशिश करेगी। यह बोझ कम हो सकता है अगर जैसा कि मैंने बताया हम अपने आपका त्याग दिखाएं और स्टेट की इकानोमी को प्लैंड तरीके सक चलाएं। आज जनता इस बात को कभी मंजूर नहीं करेगी कि स्टेट मे फजूलखर्चियां उसी तरह चलती रहें और उनकी कमाई वेस्ट होती रहे। डिवैलपमैंट के लिए जनता पर टैक्सों को बोझ डालना जयरी है लेकिन वह पैसा डिवैलपमैंट के कामों पर ही लगना चाहिए। यह प्रदेश आज हमारे अखतियार में है और यह हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए है। कहीं पर टीचर्ज की हैं, कहीं पर इंजीनियरज की हैं और अभी अभी जिन लोगों को महंगाई भता मिला है उनकी भी कितनी शिकयातें हैं। वे कहते हैं कि हमें कुछ दे तो दिया है लेकिन वह असलियत में नहीं मिला है। मसलन 50 से ऊपर तनख्वाह लेने वालों की जो आधा जमा करने वाली बात है उस से वे दुखी हैं। उनका कहना है कि कम से कम 300 रूपये तक तनख्वाह लेने वालों को तो वह पूरा मिलना चाहिए। तो मैं आप से कहता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए हमें इकानोमी की तरफ सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। लाग कहते हैं कि इस सरकार ने अभी तक इकानोमी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं तो ऐसा नहीं समझता क्योंकि राव साहिब

और फिनानस मिनिस्टर साहिब ने भी यकीन दिलाया है और बजट में भी इस का इशारा किया गया है लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा कि इस वक्त जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको हम खत्म कर रहे हैं और बिल्कुल सहने के लिए तैयार नहीं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा िकइस वक्त सबसे बड़ी मिसाल सभी लैजिसलेटर्ज मिलकर पैदा कर सकते है अगर मिनिस्टरी को जितना छोटा किया जा सके कर दिया जाए। दूसरे जितने गैर–जरूरी महकमाजात हैं और जितने उनमें गैर–जरूरी अफसर लगे हुए हैं उनको कम किया जाए। इनानोमी के लिए हमने जब शुरू किया तब नीचे से शुरू किया यानी विलेज लैवल वरकर से और जब भी सरकार ने यह कदम उठाया, जनता ने खुशी मनाई लेकिन इस ख्याल से कि बेशक यह नीचे से शुरू हुआ है पर यह बात ऊपर तक जाएगी। परन्तु देखने में ऐसा आया है कि जहां से शुरू किया वहीं खत्म हो गया। बीच तक नहीं पहुंचे ऊपर तो बहुत दूर रहा। इसलिए यह जनता की मांग है कि इस कार्यवाही को ऊपर से शुरू किया जाए। यहां पर कितने ही तीन तीन हजार लेने वाले गैर–जरूरी अफसर बिना किसी काम के रखे हुए हैं। यदि आप एक ऐसे अफसर को हटा दें तो तीस सौ सौ रूपयें लेने वाले आदमी काम कर सकते हैं। मेरा मतलब यह कि 72 आई.ए.एस. अफसर इस स्टेट के अन्दर हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह सुन कर कि 72 आई.ए.एस. अफसर यहां पर हैं। मैं नहीं समझता िकवे किस लिए यहां रखे गए हैं ? क्या जयरत है उनकी ? जबकि अपनी स्टेट का वजूद ही खतरे में है तो किस लिए इतना बड़ा सैन्टर का

लाओश्कर यहां पर रखा हुआ है। फिर सैन्टर कौन सी हमारे साथ हमदर्दी कर रहा है।

मुख्य मंत्रीः फिर क्या पटवारियों से काम लें।

चौधरी नसीब सिंहः मैं तो यह कहूंगा कि पटवारी इन लोगों से कही बेहतर हैं अगर हमारी जिन्दगी खतरे में है। अगर इस तरह की फजूलखर्ची चलती रहेगी तो चाहे कोई पटवारी, चाहे बड़ा अफसर और चाहे कोई प्रतिष्ठित राजा भी आ जाएगा तो जनता उसे बरदाश्त नहीं करेगी। तो मैं आप से कह रहा था कि इकोनामी को करें। कल ही मुझे पता लगा, खैर पते की कोई बात नहीं, वैसे ही ध्यान नहीं था।

उप–मुख्य मंत्रीः जो नकारा जमीन है, जैसा कि मैंने पहले कहा कि उसके बारे में सोचेंगे और उसको सुधारेंगे। जो हरिजन उस जमीन को लेना चाहे उनको देंगे।

चौधरी रिजक रामः जैसा कि मिनिस्टर साहिब ने कहा है कि जो नकारा जमीन है, उसको ठीक करके सरकार उसको रीकलेम करेगी या नहीं ?

उप–मुख्य मंत्रीः हां, यह अच्छी चीज है।

***253. Smt. Om Prabha Jain:** Will the Minister for Education be pleased to state the total amount accrued to the Government as Building Fund from the various Government Schools in the State, Tehsil-wise and the manner in which the Government intend to utilize this fund?

Sh. Hrdwair Lal: (a) The number of various categories of Government Schools in the State of Haryana is 5584. It would involve great labour to collect the details of Building Fund with each of these institutions which would not be commensurate with advantages likely to accrue from the collection of this information.

(b) The Building Fund rules are under the consideration of the Government and the manner in which the funds will be utilized, will be soon finalized.

श्रीमति ओम प्रभा जैनः क्या सरकार ने बिल्डिग फण्ड्ज बनाते वक्त लोकर स्कूलों के फण्ड को भी ध्यान में रखा है ?

मंत्रीः जरूर रखा गया है।

श्रीमति ओम प्रभा जैनः क्या मंत्री साहिब बतायेंगे कि जो रूपया रखा गया है उसकी डिटेल आप के पास है ?

मंत्रीः होनी चाहिए, इस वक्त है नहीं।

श्री श्रीकृष्णः क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जो फण्ड रखा गया है उस में स्कूलों के गरीब लड़कों के लिये भी कोई कंसिड्रेशन है ?

मंत्रीः मैं इस को देख लूंगा कि है या नहीं।

श्री दया कृष्णः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि जो बिल्डिंग फण्डज हैं वे कब तक इकट्ठे किये जायेंगे ?

मंत्रीः जितनी जल्दी हो सके, करेंगे। इसके लिये कोई डेट मुकर्रर नहीं है।

श्री चमन लाल गुप्ताः स्पीकर साहिब, कई स्कूल ऐसे हैं जहां फण्डज देने के बाद भी लड़कों के बैठने के लिए कोई इन्तजाम नहीं है। कई कई क्लासें बाहर बैठती हैं, बिल्डिग्ज बनाने का कोई इन्तजाम नहीं है, क्या सरकार ने ऐसे स्कूलों में बिल्डिंग्ज बनाने के लिए फण्डज रखे हैं ?

मंत्रीः यह बात दुरूस्त है लेकिन हमारे पास रिपेयर के लिये फण्डज हैं।

Student belonging to Scheduled Castes in the State

***209. Sh. Ran Singh:** Will the minister for Education be pleased to state-

a) The School-wise number of 9th, 10th and 11the class students belonging to the Scheduled Castes on Rolls of all the Higher Secondary or High Schools in Karnal District during the year 1966-67.

b) The number and names of student, out of those referred to in part (a) above, whose applications forms for

stipends were sent by the respective Headmasters/Principals to Government:

c) The number and names of students out of those referred to in part (b) above who have not been paid their stipends so far and the reasons therefore in each case?

Shri Hardwari Lal: (a) The time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits to be achieved.

(b) and (c) As at (a) above.

श्री रण सिंह: स्पीकर साहिब, मेरा सप्लीमेंटरी यह है कि जो नोवीं, दसवी और ग्याहरवीं क्लास वाले लड़के हैं उन्होने वजीफे प्रोवाइड करने के लिये बड़ी देर से दरखास्ते दे रखी है, उनको अभी तक कोई वजीफे नही मिले। मिनिस्टर साहिब ने अपने सवाल के जवाब मे लिखा है:—

"Time and labour involved in collecting the information will not be commensurate with the benefits to be achieved."

उन गरीब लड़कों को टाईम पर वजीफे ही नहें मिलते। क्या सरकार ऐसे लड़कों को वजीफे दिलाने की कोशिश कर रही है ?

मंत्री: मैं भी यही चाहता हूं कि उनके वजीफे जल्दी दिये जाये और इस मामले को खत्म किया जाये। इस पर हम सोच विचार कर रहे हैं।

Language taught in Schools

***139. Sh. Daya Krishan:** Wil the Minister for Education be pleased to state:-

a) The languages proposed to be taught upto the Middle Standard in the Schools in the State.

b) If less than five students opt to take a particular language does the Government propose to provide a teacher for that language in the said Schools?

Sh. Hardwari Lal: (a) (i) Hindi shall be taught as a compulsory subject from 1st primary class to all students irrespective of the fact whether this or any other language is their mother tongue. Hindi shall be the medium of instruction in all the Government/Recognized/ Private Schools in the State of Haryana.

(ii) English shall start from the 6th Class as heretofore as the second compulsory subject.

(iii) Sanskrit/Urdu/Punjabi shall start from the 7th Class and will be compulsory in the 7th and 8th class.

(iv) In the case of the students belonging to Punjabi/Urdu speaking minority, Punjabi/Urdu shall continue to be taught as an additional subject as heretofore in addition to Hindi from the 1st Primary Class, provided there are 10 students in a class or 40 in a Primary Department of Middle/High/Higher Secondary School who are desirous of studying Punjab/Urdu.

(b) No.

श्री दया कृष्णः स्पीकर साहिब, वजीर साहिब के जवाब के मुताबिक सातवीं क्लास के लड़कों को तीन लैंग्वेजिज पढ़नी पड़ेगी, उन में से हिन्दी और अंग्रेजी कम्पलसरी और संस्कृत, उर्दू और पंजाबी में से एक। यह जो अरेंजमेंट किया गया है यह बच्चों के लिए सूटेबिल नहीं हैं ?

श्री अध्यक्षः यह सप्लीमेंटरी कवस्चन नहीं है। यह तो एक राय है। आप कवैस्चन पूछिये।

श्री दया कृष्णः क्या मिनिस्टर साहिब बतायेंगे कि तीन लेंग्वेजिज पढ़ाने की गलत बात नहीं है ?

मंत्रीः शायद आप को याद होगा कि आपने भी इसी तरह से एजुकेशन ली थी (हंसी)

Abolition of Profession Tax imposed by the Block Samitis, etc. in the State

***138. Sh. Daya Krishan:** Will the Minister for Development be pleased to state:-

a) Whether the Government propose to abolish the profession tax imposed by the Block Samitis and Panchayat, etc, in the State; if so, the period within which it is likely to be abolished.

b) Whether the arrears of this tax are proposed not to be recovered from the persons concerned?

Sh. Partap Singh Daulta: (a) No.

(b) Question does not arise.

श्रीमति ओप प्रभा जैनः क्या इसको लिमिट के मुताबिक लगाया गया था ?

Minister: I do not know about the pahil (earlier) Ministry. But after we took over the administration of the State, we exempted all Hrijans, whether rich or poor from the payment of this tax. Further we have exempted all those, whose income is up to Rs. 1800 per year, from the payment of this tax.

श्रीमति ओम प्रभा जैनः यह जो 18 सौ तक की एग्जैम्पशन दी है, क्या मिनिस्टर साहिब बताएंगे कि वह कब से दी गई हैं ?

मंत्रीः जब से हम वजीर बने।

श्री रण सिंहः कुछ अफसरों ने बहुत से हरिजनों से टैक्स वसूल किया था, क्या मंत्री महोदय उनके खिलाफ ऐक्शन लेने के लिए तैयार है ?

मंत्रीः हमारी सरकार के बनने के बाद, कोई भी अफसर हो, या मिनिस्टर हो, उस के खिलाफ ऐक्षन लिया जाएगा अगर रूल्ज के अगैन्स्ट कार्यवाही हुई तो।

Tehsilwise Details of the Area of Land being irrigated by canals in District Hisar.

***202. Sh. Bhagwan Dev Parbhaker:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:

a) The area of land being irrigated by canals in the Hisar District tehsilwise.

b) The acreage of barani land in each of the tehsils of the said district?

c) The time by which the canal water is expected to be supplied to the said Barani land in the said District.

Sh. Mani Ram Godara: A statement is laid on the Table of the House.

Statement

(a)

Sr.	**City**	**Area irrigated by Canals in acreage**		
		Western Jamuna Canal West Circle	**Hisar-Bhakra Circle**	**Total**
1	Sirsa		847903	847903
2	Hansi	251176	86477	337653
3	Fatehabad		464330	464330

4	Hisar	21489	409103	430592
5	Bhiwani	29129	7200	36329
	Total	**301794**	**1815013**	**2116807**
(b)				
Sr.	**City**	**Barani area in acres**		
		Western Jamuna Canal West Circle	**Hisar-Bhakra Circle**	**Total**
1	Sirsa		187234	187234
2	Hansi	118824	17143	135967
3	Fatehabad		114681	114681
4	Hisar	60779	95465	706244
5	Bhiwani	495425	800	496225
	Total	**1225028**	**415323**	**1640351**

श्री भगवान देव प्रभाकारः क्या वजीर साहिब बतायेंगे कि टेल्ज पर पानी पहुंचाने का इन्तजाम किया जायेगा ?

मंत्रीः हां, कोशिश की जाएगी।

Sinking of Shallow and other Type of Tube wells at Government cost

***243. Ch. Rizaq Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

a) Whether there is any proposal under the consideration of Government to sink shallow and other type of tube wells in the State at Government cost.

b) If the reply to part (a) above be in the affirmative, the details of the above said projects together with the cost involved therein and the time by which the work on those projects is to be started and scheduled to be completed?

Sh. Mani Ram Godara: (a) Yes, of sinking deep tube wells.

(b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

Sr. No.	**Name of Scheme**	**Cost in lakhs** **RS.**	**Latest position**
1	Installation of 128 augmentation tube wells along W.J.C. from Dadupur to Munak	89.60	Project is under execution, will be completed in the year 1969-70
2	Installation of 100 augmentation tube		Scheme is to be prepared. To be

	wells along W.J.C.		executed in the 4th Plan provided funds are available
3	Installation of 100 augmentation tube wells Delhi Parallel Branch	53.12	Scheme is being finalized and is to be executed during the 4th Plan provided funds area available.
4	Installation of 100 direct irrigation tube wells along River Ghaggar		Scheme is under investigation. To be executed during the 4th Plan if funds become available.

चौधरी रिजक रामः यह जो सवाल नम्बर 243 है, इसके पार्ट 2 और 4 में जो टयूब–वैल्ज की लिस्ट दी गई है, इनकी एस्टीमेटिड कास्ट क्या हैं ?

मंत्रीः स्कीम तैयार हो जाने के बाद कुछ कहा जा सकता है।

श्रीमति ओम प्रभा जैनः जो जमीनें टेम्परेरी लीज पर हैं और जहां टयूब–वैल्ज नहीं लगाये जा सकते, वहां पर क्या सरकार अपनी तरफ से बगैर जमीन का कोई कंसीड्रेशन किए, टयूब–वैल्ज लगायेगी ?

मंत्रीः यह सवाल पैदा नहीं होता।

Electric Connections for Tube wells

***207. Sh. Ran Singh:** Will the Minister fro Irrigation and Power be pleased to state:-

a) The number of applications received so far by Government from the residents of villages Muana, Road and Danauli, Tehsil Kaithal, District Karnal for getting electric connections for their agricultural tube wells.

b) The action so far taken on the said applications?

Major Amir Singh (Minister of State for Rural Electrification): (a)

1. Muana	5 Nos.
2. Rodh	18 Nos.
3. Danauli	Nil

(b) The estimates in respect of al the applications of Muana Village are under preparation in the Electricity Board

and due action will be taken after the requisite formalities are completed.

Out of 18 applications of village Rodh, the work of 5 applications has since been completed and due action will be taken after the inspection of the Electrical Inspector. In other cases of this village the estimates are being prepared and needful will be done in due course of time.

श्री रण सिंहः मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं कि दरखास्तें कितनी देर से पेंडिंग हैं ?

राज्य मंत्रीः मुझे इसके लिये नोटिस चाहिए।

श्री रण सिंहः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि उनहोंने कोई टाइम निश्चित किया है कि इतनी देर के बाद कम्पलांइस हो जायेगी ?

राज्य मंत्रीः सामान और रूपया अगर हो तो उसी वक्त कम्पलाइंस हो जायेगी।

Electric Connections for Tube wells

***208. Sh. Ran Singh:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

a) The criteria laid down for fixing priority in respect of applications received by the Government in the State for granting electric connections to Agricultural tube wells.

b) The cases in which the Government gives preference?

Sh. Mani Ram Godara: (a) & (b) A statement is laid on the Table of the House.

Statement

The priorities and preference for granting electric connections to agricultural tube wells are governed by the following criteria:-

i. Higher priority to applicants for areas which are not commanded by canals.

ii. Next higher priority to areas which receive non-perennial irrigation.

iii. For Lift irrigation, etc., to those applicants whose lands area acquired/submerged for (i) power projects or (ii) the common works in the case of multipurpose projects, such as dam, etc.

iv. Defence personnel on active service as well as those killed or disabled in action, provided the application is in his name or in the name of his father, mother, wife or dependent children and the applicant has/had an interest in the land commanded by the pumps or tube wells.

v. (a) Co-operative faming societies and co-operative processing societies.

(b) Panchayats.

(c) State tube wells installed for irrigation purposes.

Tube wells Connections

***244. Ch. Rizaq Ram:** Will the Minister for Irrigation and Power be pleased to state:-

a) The total number of application for tube well connections at present lying pending in the State.

b) The number out of the above said application in which test reports have been received.

c) The number of applications for tube well connections rejected as being unjustifiable during the year 1966-67?

Major Amir Singh (Minister of State for Rural Electrification): (a) 14104.

(b) 2318.

(c) 1586.

Names of the Newspapers, Dailies, Weeklies and Monthlies Inside and outside the State which have been paid advertisement charges since 1st January, 1966.

***200. Sh. Bhagwan Dev Parbhakar:** Will the Minister for Transport be pleased to state the names of the newspapers, dailies, weeklies and monthlies published in the

State, Tehsil wise, as well as those published outside the State which were given Government advertisements and the details of the amount paid to them on that account separately during the period from 1st January, 1966 up to date?

Sh. Lachhman Singh: A statement showing particulars of papers with cost of advertisements released for the period from 1st November, 1966 to 30th April, 1967, is placed on the Table of the House.

Since the Haryana State came into existence on the 1st November, 1966 the desired information is being supplied for the period from 1st November, 1966 to 30th April, 1967.

STATEMENT

Sr.	**Name of paper/ periodical**	**Place/Tehsil from where published**	**Amount**
1	**2**	**3**	**4**
I-Papers/ Periodicals Published inside the State			**Rs.**
(a) English			
1	Tribune	Ambala	23619.20
(b) Hindi			
1	Vir Partap	Ambala	3351.09

2	Mewat	Gurgaon	1125.32
3	Sunehri Bharat	Gurgaon	1000.40
4	Haryana Tilak	Rohtak	643.00
5	Purvi Punjab	Bhiwani	157.20
6	Haryana Darpan	Karnal	505.17
7	Gyanodey	Hisar	535.28
8	Bharat Darshan	Palwal	223.84
9	Haryana Sandesh	Hisar	51.92
10	Chetna	Bhiwani	82.50
(c) Urdu			
1	Haryana Tilak	Rohtak	315.00
2	Jat Gzette	Rohtak	430.40
3	Janam Bhoomi	Karnal	100.10
4	Awaz-e-Hind	Ambala	45.54
5	Ambalal Times	Ambala	284.13
6	Mewat	Gurgaon	221.24
7	Roshni	Sonepat	68.97
8	Bharat Tek	Rohtak	55.06

9	Prem Marg	Ambala	60.50
10	Tehqiqat	Rohtak	134.97
II-Papers/Periodicals published outside the State			**Rs.**
(a) English			
1	Indian Express	Delhi	11650.90
2	Patriot	Delhi	4068.80
3	Hindustan Times	Delhi	5488.71
4	Times of India	Delhi	2816.00
5	Hindu	Madras	338.80
6	Indian Express	Bombay	317.62
7	Amrit Bazar Patrika	Calcutta	488.40
8	Caravan	Delhi	264.00
9	Link	Delhi	701.50
10	National Star	Delhi	228.15
11	National Solidarity	Delhi	209.44
12	Rajasthan Public Relations Assn.	Jaipur	250.00

13	Seventh All India Children Conf.	Delhi	250.00
14	Guru Gobind Singh Foundation	Chandigarh	500.00
15	Eastern Economist	Delhi	175.00
16	Statesman	Delhi	422.40
17	Punjab Sentinel	Chandigarh	122.40
18	Socialist Congressman	Delhi	360.00
19	All India Congress Committee	Delhi	200.00
20	INTUC	Delhi	400.00
21	Haryana United Nations Asson.	Rohtak	220.00
22	All India Small and Medium Newspaper Editors Association	Kanpur	200.00
23	Indian News and Feature Alliance	Delhi	300.00

24	Shankar Weekly	Delhi	345.58
(b) Hindi			
1	Milap	Jullundur	2018.16
2	Nav Bharat Times	Delhi	2147.20
3	Vir Arjun	Delhi	2059.20
4	Hindustan	Delhi	4604.00
5	Jagrat Haryana	Delhi	74.36
6	Hindi Times	Delhi	724.58
7	Punjab Kesri	Jullundur	996.30
8	Sewagram	Delhi	687.28
(c) Urdu			
1	Milap	Jullundur	2113.32
2	Partap	Delhi	3053.56
3	Tej	Delhi	1783.02
4	Savera	Delhi	917.28
5	Hind Samachar	Jullundur	1087.48
6	Jagat	Delhi	18.48
7	Parbhat	Jullundur	35.90

8	Partap	Jullundur	628.60
9	Pardeep	Jullundur	495.00
10	Rohjan	Ludhiana	60.50
11	Hindu	Jullundur	210.10
12	Atalique	Delhi	47.85
13	Lalkar	Delhi	95.70
14	Bhartiya Spoot	Delhi	60.50
15	Punjab Congress Patrika	Chandigarh	102.30
16	Jan Nissar	Delhi	127.50
17	Missihi Duniya	Delhi	46.75
18	Biswin Sadi	Delhi	170.00
19	Motor Transport Gazette	Chandigarh	224.00
20	Driver	Jullundur	280.00
21	Transport Worker	Delhi	60.00
22	Transport Gazette	Delhi	240.00
23	Motor Transport Worker	Jullundur	40.00

(d) Punjabi			
1	Ajit	Jullundur	733.60
2	Ranjit	Patiala	233.64
3	Nawan Hindustan	Delhi	641.24
4	Mel Milap	Chandigarh	289.41
5	Akali Patrika	Jullundur	750.20
6	Nawan Zamana	Jullundur	182.79
7	Lok Darshan	Delhi	119.16
8	Parkash	Chandigarh	189.69
9	Sikh	Amritsar	60.50
10	Fateh	Delhi	46.20
11	Ranjit Nagara	Chandigarh	60.50
12	Panth Parkash	Delhi	123.20
13	Mauji	Jullundur	84.80
		Total	**92102.98**

श्री भगवान देव प्रभाकरः क्या मंत्री महोदय बतायेंगे कि कांग्रेस के शासन में प्लैन्ज के बारे में जो पक्षपात से काम लिया गया है, वह पक्षपात अब दूर किया जायेगा ?

श्री अध्यक्ष: कवैस्चन ओवर हो गया।

मैं हाउस की जानकारी के लिए यह बताना चाहता हूं कि जिन सवालों के जवाब नहीं आये हैं उनके लिये मिनिस्टर साहिबान मण्डे को प्रिपेयर होकर आयेंगे।

UNSTARRED QUESTION AND ANSWERE

National Defence Fund Collected by the Kurukshetra University

***23. Sh. Om Parkash:** Will the Minister for Education be pleased to state the amount of National Defence Fund collected by the Kurukshetra University together with the amount left after bearing of the expenses of the Kurukshetra University Canteen for Jawans and also the date when the remaining amount was deposited by the University with the National Defence Fund authorities?

Sh. Hardwair Lal:	**Rs.**
Receipt during 1965-66	6449.90
Expenditure during 1965-66	5402.46
(For running Canteen for Jawans)	401.46
Presented to Chief Minister, Punjab	5001.00
Receipt during 1966-67	26.00
Expenditure during 1966-67	Nil

The balance amounting to Rs. 1073.44 lying with the University has been remitted to the National Defence Fund on 8th June, 1967.

CALL ATTENTION NOTICE

Sh. Daya Krishan: My call Attention notice regarding hunger-strike by public servants stands admitted by you but so far no statement thereon has been made by the Government. Would you kindly request the Government to make a statement about it?

श्री अध्यक्षः हां जी, मुख्य मंत्री साहिब को चाहएि था इस का जवाब दे देते।

मुख्य मंत्रीः स्पीकर साहिब, अभी तो कोई भूखहड़ताल हुई नहीं, न ही कोई मरा है। श्री दया कृष्ण जी खाना ले कर जाते हैं, उनके लिये। जब कोई बात होगी तो सोचेंगे।

GENERAL DISCUSSION ON THE BUDGET (Resumption)

श्री गणपत (एस.सी., दादरी): स्पीकर साहिब, बजट पर कुछ कहने से पहले मैं प्रैस की मारफत हाउस को बताना चाहता हूं कि मरा संकट दल से कोई सम्बन्ध नहीं है और मैं कांग्रेस पार्टी में हूं।

Development Minister: On a point of order, Sir. Can any member address Press persons from the floor of the House? He cannot do so. In the House he can address the Speaker and none else.

Mr. Speaker: This is not relevant. I would request the Hon. Member to speak on the Budget.

श्री गणपत रायः स्पीकर साहिब, बजट में हरिजनों के लिये 70 लाख रूपया रखा गया है जो कि मैं समझता हूं बहुत कम है। मैं इस बात को मानता हूं कि सरकार की मजबूरियां होती हैं, इसलिये यह अधिक धन राशि नहीं दे सकी। लेकिन कुछ और ऐसे तरीके हैं जिन कोअगर अपनाया जाये तो सरकार के पास काफी पैसा आ सकता है और हरिजनों का अगर सरकार कल्याण करना चाहे तो कर सकती है। लेकिन आज हम देख रहें हैं कि हरिजनों की बुरी तरह से एक्सप्लाएटेशन हो रही है। आज हरिजन बर्ग तथा मजदूर वर्ग जो नहरों, सड़कों तथा दूसरे पुलों वगैरा पर काम करते हैं उन की भलाई की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा। अगर सरकार उस तरफ ध्यान दे तो उनकी हालत सुधर सकती हैं।

मुख्य मंत्रीः इधर आ कर ध्यान करने लग जाओ तब सुधर जाएगी।

श्री गणपत रायः स्पीकर साहिब, आज नहरों पर, भट्टों पर जो ठेकेदार हैं, वह मजदूरों की मेहनत से अपनी झोलियां भर रहे हैं। आज मजदूरों की वर्किंग कंडीशन्ज बहुत खराब हो चुकी

है और जो 1947 से पहले उनके वेतन थे वही वेतन उन्हें आज भी मिल रहे हैं। अगर सरकार ईमानदारी से कोशिश करे तो बिना जनता पर बोझ डाले उन की हालत को सुधार सकती है। दूसरा मसला हरिजनों को सरप्लस जमीनें देने का है। आज यह उनके लिए स्वपन बर कर रह गया है कि उन को कभी जमीनें मिलेंगी। हरिजनों को जमीनें दिलाने के लिए सरप्लस लैंड का कानून तो बना लेकिन उस के साथ ही अमैंडमैंट ला कर एक हाथ से जो चीज दी थी वह दूसरे हाथ से छीन ली ई और सरप्लस जमीन का मसला एक धोका बन कर रहा गया और जो बड़े जमींदार थे जिन के पास हजारों एकड़ जमीन थी आज वह उन्हीं के पास बनी है। इसी तरह नजूल जमीन और पंचायतों की जमीनों में भी धांधली मची हुई है। इवैक्वी लैंड का जहां तक ताल्लुक है उसकी आक्शन हुई थी। .....

Mr. Speaker: No interruption please.

श्री गणपत रायः स्पीकर साहिब, बहुत से ऐसे केसिज हैं, हरिजनों ने नीलामी में जमीनें लीं लेकिन 3/4 सालों से उन्हें पोजैशन नहीं मिल रहा और नायब तहसीलदार हरिजनों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। बहुत से खेतों के उन को गलत नम्बर दे दिए गए जिस की वजह से उन्हें पोजैशन नहीं मिल रहा है। अगर हमारी सरकार और उनके अफसर नेकनीयती से काम करें तो उन की ऐसी तकलीफें दूर हो सकती हैं।

इस बजट स्पीच में छुआ छूत दूर करने का जिक्र किया गया है। आज हमें आजादी मिले को 20 साल हो गये हैं लेकिन अफसोस से कहना पड़ता है कि आज भी छुआ छूत उसी तरह से चल रही है। आज एक हरिजन गांव के कामन कुएं से पानी नहीं ले सकता। मैं निवेदन करूंगा कि अगर हालात ठीक न किए गए तो बहुत मुश्किल हो जायेगी।

छूआछूत का जहां तक हाल है कि स्कूलों में हरिजनों को चपड़ासी तक नहीं रखा जाता है क्योंकि हैडमास्टर समझतें हैं कि अगर इनको रखेंगे तो इनके हाथ से पीने से धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। अगर हरिजनों के साथ आजादी के बाद भी यही सलूक होता रहा तो इस आजादी का उनको क्या फायदा है ?

(At this stage Mr. Deputy Speaker occupied the Chair.)

हरिजन स्टूडैंट्स को जो वजीफें दिए जाते हैं उन में बड़ी धांधली चलती है। सारा साल गुजर जाता है लेकिन वजीफा नहीं मिलता है। इसके इलावा मंहगाई इतनी हो गई है लेकिन वजीफों को शरह वही है जो 1947 में फिक्स की गई थी। इस रकम से गुजारा नहीं होता है इस लिए इस शरह में बढ़ोतरी होनी चाहिए। इसी तरह हरिजन स्टूडैंट्स को जो करजे दिए जाते हैं उस में भी बुरा हाल हैं। सैशन के शुरू से ही इतनी दरखासतें ऐजुकेशन डिपार्टमैंट को आई हुई हैं लेकिन कोई गौर नहीं किया जाता है। फिर हरिजन वैलफेयर डिपार्टमैंट में जो धांधली चल रही

है उसकी तरफ ध्यान देने की जरूरत है। मैं अर्ज करता हूं कि जो हरिजनों की दशा सुधारने के ठेकेदार बने हुए हैं, उनकी दशा सुधारने का बड़ा दावा करते हैं और पिछले बोस साल से यह ठेकेदार आपने हाथ में रखे हुए हैं अगर इस सरकार में हिम्मत है तो मेरी दरखासत है कि हरिजन वैलफेयर डिपार्टमैंट उस ठेकेदार मिनिस्टर से ले लें और दौलता साहिब को दे दें या और दूसरे मिनिस्टर को दे दें लेकिन यह बीमारी जिन्होंने बढ़ाई है उन से यह महकमा ले लें।

चौधरी नसीब सिंह (कलानौर): डिप्टी स्पीकर साहिब, आज इस बजट पर बहस का तीसरा दिन चल रहा है और इस पर काफी बहस हो चुकी है। इस बजट को कई किस्म के नामों से पुकारा गया है लेकिन बाहर जब प्राइवेट तौर पर बात होती है तो आपोजीशन वालों को भी यह कहते सुना है कि बजट तो अच्दा बना है मगर मुखालफत तो करनी ही है। मैं उन से यह कहना चाहता हूं कि आप मुखालफत के लिए मुखालफत बेशक कर लें लेकिन पिछली सरकारों के बीस सालों के बजटों से अब मुकाबला करते हैं तो पता लगता है कि यह बजट सही मायनों में अकालियों में दब कर रहने वाली इस बंटवारे में हरियाणा से बेइन्साफी कराने वाली और बीस साल तक गलत नीतियों पर चलने वाली कांग्रेस सरकार के बजटों से अच्छा है और इस छोटे से उजड़े प्रांत की गरीब जनता की आशाओं का आइना है और बड़ी दूर देशों से तैयार किया गया है। इस बजट में तमाम पहलुओं को जरूरत के

मुताबिक और योजना के अनुसार कबर किया गया है। इसलिए यह अब तक के बजटों में से सबसे अच्छा है। कुछ टैक्सों के बारे में आपोजीशन की तरफ से वावेला किया गया है। इस में शक नहीं कि हरियाणा की जनता जो काफी दिनों से पिस रही थी और टैक्स ही टैक्स दे रही थी जिसके बदले उसे कुछ मिल नहीं रहा था उसकी बढ़त ज्यादा इच्छा और भावना इन टैक्सों से बचने की थी और वह समझती थी जब हरियाणा बनेगा तो इस कमर तोड़ टैक्सों से उसे राहत मिलेगी। कोई सूझबूझ रखने वाला आदमी समझ सकता है कि यह टैक्स ही हरियाणा की पैदायश के साथ पैदा हुए हैं। इतना छोटा सा सूबा जिसके अन्दर पिछले बीस साल में कोई डिवैलपमैंट नहीं हुई, आमदनी का कोई जरिया नहीं पैदा किया गया और न पैदा होने दिया गया। वह किस तरह बगैर टैक्सों के चल सकेगा, यह बात सभी जानते थे कुछ दूरअंदेश आदमी इसी डर से पंजाबी सूबा बनाने की मुखालिफत भी करते थे क्योंकि हरियाणा का जो इलाका रह जाएगा वह समझते थें कि वह अपने पैरों पर खड़ा होने के लिए मुशकिल में पड़ जाएगा और जनता पर भारी टैक्स लगाने पडेंगे। इसलिए अब टैक्सों की मुखालिफत करना और उन से डरना समझ में आने वाली बात नहीं। पिछली सरकार ने जनता की तकलीफों की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। और वह तो इस बात की आदी थी कि जनता रोती रहे और वह अपनी चाल चलते रहें लेकिन जो नई सरकार बनी है इसे जनता की तकलीफों की तरफ ध्यान देना पड़ेगा। मैं निवेदन करूंगा कि आज हरियाणा में रैवोलूशन हुई है और जनता में जो

जोश पैदा हुआ है कि हम अपने सूबे की तरक्की करेंगे और देश की दूसरी स्टेट्स के बराबर दरजा हासिल करेंगे वह जोश हमने कायम रखना है और इसके लिए हमें प्रयत्न करना पड़ेगा, उसके लिए बड़ी से बड़ी कुरबानी करनी पड़ेगी, बड़े से बड़ा त्याग करना पड़ेगा और हम सारे लैजिस्लेटर्ज को सारे प्रदेश के लिए एक हो कर काम करना पड़ेगा और हम सारे लैजिस्लेटर्ज को सारे प्रदेश के लिए एक हो कर काम करना पड़ेगा वरना यह हमारा अपना अपना सवाल कि मेरी हकूमत बनी है तो यह अब क्यों छिन जाए और अब मेरी ही बनी रहे अगर इनहीं झगड़ों में और जोड़ तोड़ में हम लगे रहे तो हमरार प्रदेश तकरक्की नहीं कर सकेगा, तरक्की के साधन नहीं जुटाए जा सकेंगे और इस प्रदेश की जिन्दगी और इज्जत खतरे में पड़ जाएगी। इसलिए आज इस बात की सख्त जरूरत है कि हमें सारे ही लैजिस्लेटर्ज को एक हा कर इस प्रदेश के लिए मेहनत करनी चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि यह जो टैक्स लगे हैं इनके बारे में सोचना है कि क्या यह हमारे प्रदेश की तरक्की के लिए जरूरी है या नहीं। सरकार ने जनता की भावनाओं का आदर करते हुए आब्याना टैक्स है और कुरूक्षेत्रयूनिवर्सिटी की लिए जो मालगुजारी बढ़ाई है चाहे एक साल के लिए बढ़ाई है उसे भी जनता बोझ समझती है। एक साल के लिए तो जनता बोझ उठाने के लिए तैयार है लेकिन डर इस बात का है कि कहीं पिछली सरकार की पैरवी करते हुए यह टैक्स पक्का ही न हो जाए जिस तरह वह एक साल का बहाना लगाकर बाद में टैक्स पक्का कर देती थी। इस लिए जनता आशा करती है

कि यह सरकार अपने वायदे के अनुसार अगले साल यह टैक्स हटा लेगी। जनता सरकार ये यह भी आशा करती है कि इन टैक्सों से लिया एक एक पेसा वह बचाएगी और उसका बोझ कम करने की कोशिश करेगी। यह बोझ कम हो सकता है अगर जैसा कि मैंने बताया हम अपने आपका त्याग दिखाएं और स्टेट की इकानोमी को प्लैंड तरीके सक चलाएं। आज जनता इस बात को कभी मंजूर नहीं करेगी कि स्टेट मे फजूलखर्चियां उसी तरह चलती रहें और उनकी कमाई वेस्ट होती रहे। डिवैलपमैंट के लिए जनता पर टैक्सों को बोझ डालना जयरी है लेकिन वह पैसा डिवैलपमैंट के कामों पर ही लगना चाहिए। यह प्रदेश आज हमारे अखतियार में है और यह हमारा ऐडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए है। कहीं पर टीचर्ज की हैं, कहीं पर इंजीनियरज की हैं और अभी अभी जिन लोगों को महंगाई भता मिला है उनकी भी कितनी शिकयातें हैं। वे कहते हैं कि हमें कुछ दे तो दिया है लेकिन वह असलियत में नहीं मिला है। मसलन 50 से ऊपर तनख्वाह लेने वालों की जो आधा जमा करने वाली बात है उस से वे दुखी हैं। उनका कहना है कि कम से कम 300 रूपये तक तनख्वाह लेने वालों को तो वह पूरा मिलना चाहिए। तो मैं आप से कहता हूं कि इन सब बातों को देखते हुए हमें इकानोमी की तरफ सबसे पहले ध्यान देना पड़ेगा। लाग कहते हैं कि इस सरकार ने अभी तक इकानोमी की तरफ ध्यान नहीं दिया। मैं तो ऐसा नहीं समझता क्योंकि राव साहिब और फिनानस मिनिस्टर साहिब ने भी यकीन दिलाया है और बजट में भी इस का इशारा किया गया है लेकिन इतना मैं जरूर कहूंगा

कि इस वक्त जो फिजूलखर्ची हो रही है उसको हम खत्म कर रहे हैं और बिल्कुल सहने के लिए तैयार नहीं। तो मैं एक बात बताना चाहूंगा िकइस वक्त सबसे बड़ी मिसाल सभी लैजिसलेटर्ज मिलकर पैदा कर सकते है अगर मिनिस्टरी को जितना छोटा किया जा सके कर दिया जाए। दूसरे जितने गैर–जरूरी महकमाजात हैं और जितने उनमें गैर–जरूरी अफसर लगे हुए हैं उनको कम किया जाए। इनानोमी के लिए हमने जब शुरू किया तब नीचे से शुरू किया यानी विलेज लैवल वरकर से और जब भी सरकार ने यह कदम उठाया, जनता ने खुशी मनाई लेकिन इस ख्याल से कि बेशक यह नीचे से शुरू हुआ है पर यह बात ऊपर तक जाएगी। परन्तु देखने में ऐसा आया है कि जहां से शुरू किया वहीं खत्म हो गया। बीच तक नहीं पहुंचे ऊपर तो बहुत दूर रहा। इसलिए यह जनता की मांग है कि इस कार्यवाही को ऊपर से शुरू किया जाए। यहां पर कितने ही तीन तीन हजार लेने वाले गैर–जरूरी अफसर बिना किसी काम के रखे हुए हैं। यदि आप एक ऐसे अफसर को हटा दें तो तीस सौ सौ रूपयें लेने वाले आदमी काम कर सकते हैं। मेरा मतलब यह कि 72 आई.ए.एस. अफसर इस स्टेट के अन्दर हैं मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ यह सुन कर कि 72 आई.ए.एस. अफसर यहां पर हैं। मैं नहीं समझता िकवे किस लिए यहां रखे गए हैं ? क्या जयरत है उनकी ? जबकि अपनी स्टेट का वजूद ही खतरे में है तो किस लिए इतना बड़ा सैन्टर का लाओश्कर यहां पर रखा हुआ है। फिर सैन्टर कौन सी हमारे साथ हमदर्दी कर रहा है।

मुख्य मंत्रीः फिर क्या पटवारियों से काम लें।

चौधरी नसीब सिंहः मैं तो यह कहूंगा कि पटवारी इन लोगों से कही बेहतर हैं अगर हमारी जिन्दगी खतरे में है। अगर इस तरह की फजूलखर्ची चलती रहेगी तो चाहे कोई पटवारी, चाहे बड़ा अफसर और चाहे कोई प्रतिष्ठित राजा भी आ जाएगा तो जनता उसे बरदाश्त नहीं करेगी। तो मैं आप से कह रहा था कि इकोनामी को करें। कल ही मुझे पता लगा, खैर पते की कोई बात नहीं, वैसे ही ध्यान नहीं था। अपनी छोटी सी स्टेट बन गई। पंजाब के बाद स्टेट क्या बन गई एक डिवीजन रह गया। पहले हमारा जितना अम्बाला डिवीजन होता था उसकी तरह यह स्टेट बन गई है। इसका हैडक्वार्टन भी बन गया है। सारे जिलों का इस से सीधा सम्बन्ध है। फिर मैं नहीं समझता कि डिवीजनल हैडक्वार्टरज जो हैं उनकी और उनके अन्दर जो लाओ लश्कर बैठा है उसकी क्या जरूरत रह गई है। इनकी कतई जरूरत नहीं है। इसलिए मैं पुरेजोर लफ्जों में कहता हूं कि यह जनता की मांग है कि इस वक्त इकोनोमी की जरूरत है और जिन लोगों के ऊपर यह बोझ डाला है अगर उनसे सरकार को कोई हमदर्दी है तो यह गैर–जरूरी जितने महकमाजात हैं इन्हें फौरन तोड़ दिया जाए। मेरा यहां यह कहने से मतलब किसी की शान के खिलाफ कुछ कहने से नहीं है। मैं तो यह स्टेट की इकोनामी के लिए बात कर रहा था। आई.ए.एस. अफसर हमारे मोहतरिम एफसर हैं और उनको जो ड्यूटीज दी हुई हैं उनको वे करते हैं। हो सकता है

कि बीच में एक आधा आदमी लापरवाही भी करता हो। लेकिन जनता इस बात को चाहती है कि जो महकमेजात या जो अफसर गैर जरूरी हैं उनको खत्म कर दिया जाए। फिर एक आदमी की डबल अप्वायंटमैंट जो है कि एक ही आदमी हैड आफ दी डिपार्टमैंन्ट और सैक्रेटरी दोनों होंख इस से डिपार्टमैंट के अन्दर काम में रूकावट आती हैं, फैसला लोगों को सही नहीं मिल सकता मिनिस्टर से और चीफ मिनिस्टर, से उस डिपार्टमैंट का ताल्लुक नहीं हो सकता और उनके जो टैक्नीकल हैड्ज आफ डिपार्टमैंन्ट्स और डिप्टीज हैं उनकी तजवीजें उनको मिल नहीं सकता। तो मेरा आप से निवेदन है कि स्टेट के अन्दर इकानोमी लोने के लिए हमें इन सब बातों पर विचार करना पड़ेगा और सब बातों पर विचार करने के बाद हमें इस बात के लिए तैयार होना पड़ेगा कि गरीब जनता के ऊपर ये टैक्स जो है, ये जितने ज्यादा हो सकें कम किए जाएं। आगे बढ़ाने की कतई गुंजायश नहीं है।

इसके बाद उपाध्यक्ष महोदय मैं एक बात अर्ज करना चाहूंगा कि यह जो हरिजन भाई चाहे वह अमीर हो चाहे गरीब हो, एक से समझे जाते हैं यह बात ठीक नहीं। मेरी हरिजनों से कोई दुश्मनी नहीं लेकिन मैं एक जायज बात कर रहा हूं। इस साल जो इनकी भलाई के लिए 72 लाख रूपया रखा गया है उससे भी मेरे भाई सनतुष्ट नहीं हैं। मैं तो कहता हूं कि आज हरिजन और नान–हरिजन का सवाल कतई बाकी नहीं रहा है। आज तो गरीब और अमीर का सवाल है। हरिजन यदि गरी हैं तो वह तो उस

केटेगरी में आते ही रहे हैं लेकिन रामधारी जी और चान्दर राम जी ये क्यों आएं उस केटेगरी में और यदि आते हैं तो यह साफ डिस्क्रिमिनेशन है। यह नहीं होना चाहिए। आर्थिक तौर से जो भी इस केटेगरी में आते हैं, चाहे वह कोई भी है, उनहें हिस्सा मिलना चाहिए। सबके साथ बराबर सलूक होना चाहिए। जो आर्थिक तौर पर बराबर है, वे सब बराबर हैं, चाहे वे हरिजन हैं या गैर–हरिजन हैं (विघ्न)

श्री उपाध्यक्षः नो इंट्रप्शन प्लीज।

चौधरी नसीब सिंहः अब मैं सिर्फ इतना निवेदन करूंगा कि जनता कोई जादू नहीं चाहती, हमारे से कोई पहाड़ गिरवाना नहीं चाहती। वह तो सिर्फ इतना चाहती है कि सरकार के अन्दर उनकी सुनवाई हो। इस में कोई शक नहीं कि संयुक्त दल की सरकार को अभी तक बहुत कम टाइम मिला है लेकिन इसे यह भी स्वीकार कर लेना चाहिए कि अभी तक इसने बहुत कम कदम बढ़ाए हैं। अभी तक जिस तरह से कांग्रेस राज के अन्दर उनकी सुनवाई नहीं थी उसी तरह इस राज में भी अभी तक उनकी सुनवाई नहीं है और रिश्वत ली जा रही है। खास तौर पर देहात के अन्दर तो एक महकमा नहरों को और दूसरा महकमा सप्लाई का ऐसा है जिसमें खुले आम रिश्वत ली जाती है। (एक आवाज– बिजली का भी है) हां बिजली का भी है लेकिन ये दो कुछ ज्यादा हैं। इसकी तरफ मोहतरिम वजीर जो है। वे ध्यान दें और जाकर जनता की तकलीफ सुनें। मुझे इस बात का अफसोस है कि अभी

तक मोहतरिम वजीर जो हैं, वे किसी और डिस्ट्रिक्ट में गए हैं हों तो पता नहीं, उन्होंने रोहतक में जाकर अभी तक एम.एल.एज. को इकट्ठा करके, उस डिस्ट्रिक्ट की क्या प्रोब्लम्ज हैं, क्या तकलीफें हैं, यह नहीं सुना। इसलिए मैं दर्खास्त करता हूं कि इसको जल्दी से जल्दी किया जाना चाहिए ताकि देश तरक्की करें। जो विधान सभा में 81 के 81 एम.एल.ए. बैठे हुए हैं उनको अपने आप को मिनिस्टर समझना चाहए ताकि जिस किसी कांस्टीच्यूऐसी में कुरप्शन हो रही हो, भ्रष्टाचार हो और डिस्क्रिमिनेशन हो, उसकी पूरी पूरी जिम्मेदारी लेकर देश के एिल काम करें। डिप्टी स्पीकर साहिब .....

श्रीमति ओम प्रभा जैनः ये जो कई मिनिस्टर साहिब रिलीफ फण्ड का नारा लगाते हैं और खुद कुरप्शन करते हैं। उस रूपये को कहीं जमा ही नहीं किया गया है। उन को कौन पकड़ेगा ? (शोर)

चौधरी नसीब सिंहः इस बात का सभी को पता है, यह मिनिस्टर साहिब भी जानते हैं ।

श्री उपाध्यक्षः नो इन्ट्रप्शन प्लीज।

चौधरी नसीब सिंहः अब मैं निवेदन करना चाहता हूं कि देहात के अन्दर आमतौर पर जनता की तरफ से यह आवाज उठाई जा रही है कि बैटरमैंट लैवी को खत्म किया जाए। बहुत दिनों से जनता को यह उम्मीद थी कि नई सराकर किसानों की बेहतरी के

लिए अच्छे कदम उठाएंगी। इसलिए मैं सरकार से दर्खास्त करता हूं कि जिस बैटरमैंट लैवी को आप जस्टीफाईड कहत हैं वह अनजस्टिफाईड है। इसलिए यह किसानों पर न लगाकर किसी और तरीके से लगाया जाए। आज देश फूड की प्राब्लैम है, इसकी जिम्मेदारी किसी पर्टिकुलर वर्ग पर नहीं आती बल्कि री नेशन पर आती है। किसान सारे देश के लिए काम करता है इसकी साहयता करना सब का फर्ज है। इस की जो जायज मांग हो और जो जो मुश्किलात उसके खाते में हो उनको दूर करना हमारा फर्ज है।

(डिप्टी स्पीकर साहिब ने राव जसवन्त सिंह का नाम पुकारा)

ग्राम्य विद्युतीकरण राज्य मंत्रीः डिप्टी स्पीकर साहिब, आपने मुझे आज तक बोलने के लिए टाइम नही दिया मुझे टाइम मिलना चाहिए।

श्री उपाध्यक्षः आप इनके बाद बोल लेना।

श्री जसवन्त सिंह (जातूसाना): डिप्टी स्पीकर साहिब, पिछले दिनों हमारे फिनांस मिनिस्टर साहिब ने रिवाड़ी में तकरीर की। तकरीर के बाद मैं रिवाड़ी में गया और लोगों से यह जानने की कोशिश की कि सरकार के मुताल्लिक लोगों की क्या राय है। मुझे मालूम हुआ कि लोग यह महसूस कर रहे हैं कि रिवाड़ी के इलाके मेंबहुत अर्से से कोई तरक्की नहीं हुई है। फिनांस मिनिस्टर साहिब की तकरीर सुनने से इस बात की पुष्टि हो गई। सन् 1947

में आजादी मिलने के बाद और उससे पहले रिवाड़ी शहर जिला के प्रमुख शहरों में से एक था। खेतीबाड़ी के लिहाज से व्यापार के लिहाज से और दूसरी बातों के लिहाज से सबसे आगे था, लेनि उसके बाद कोर्ठ तरक्की नहीं हुई। एक समय आया था जब वहां कुछ सड़कें बनीं और बिजली की तारें भी लगीं। बिजली के बारे में यह है कि बिजली इतनी कमजोर है कि अक्सर बन्द रहती है। अगर कभी आती भी है तो उसकी वोलटेज बहुत कम होती है जिससे कारखाने वगैरह नहीं चल सकते, छोटे मोटे रेडियों और पंखे ही चलते हैं। बिजली की सप्लाई ठीक न होने के कारण पानी की व्यवस्था बहुत खराब हैं। हमारे इलाके के लोग यह समझते थे कि संयुक्त दल की सरकार बन गई है, इसलिए गुड़गांव जिला की तरक्की के लिए स्कीमों को अमलीजामा पहनाएगी, लेकिन फिनांस मिनिस्टर साहिब की तकरीर सुनने क बाद इस की कोई आशा नहीं रहीं। गुड़गांव जिला की तरक्की के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। सरकार कहती है कि हम ट्यूबवैल्ज लगा रहे हैं। पहले इस इलाके में कुछ ट्यूबवैल्ज लगाए गए थे लेकिन उसके बाद इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया। इस तरह से इस इलाके को बिल्कुल इगनोर कर दिया गया है।

डिप्टी स्पीकर साहिब, जहां तक इंडस्ट्री का ताल्लुक है इस लिहाज से भी यह जिला पीछे है। जो कालेज वगैरा बनाया गया है वह फरीदाबाद में बनाया गया है। जो भी इंडस्ट्री की

थोड़ी बहुत डिवैलपमेंट हुई है वह फरीदाबाद में ही हुई है और इस इलाके को इगनोर कर दिया गया है।

जहां तक टैक्सिज का ताल्लुक है, यह सभी जानते हैं कि इस महंगाई के जमाने में टैक्सेशन लगाना एक ज्यादती है, लेकिन हम यह अच्छी तरह जानते हैं कि हमारी सरकार पैसे के लिहाज से मुश्किल में है क्योंकि हरियाणा प्रान्त को बने हुए अभी सात आठ महीने ही हुए है। इसका कारण यह भी है कि हरियाणा के पास इरीगेटड लैंड कम है। लेकिन फिर भी जो लैंड रैवेन्यू किसानों पर लगाया गया है वह लोगों के साथ ज्यादती है। जिस जमीन में धूल उड़ती हो, कुछ पैदा न होता हो, वहां लैंड रैवेन्यू नहीं लगना चाहिए।

जहां तक आबयाना टैक्स का ताल्लुक है, उसको खत्म करने में सरकार की सराहना करता हूं कि उन्होंने एक अच्छा कदम उठाया। मैं आशा करता हूं कि हमारी सरकार ऐसे ही जमींदारों के लिए अच्छे कदम उठाया करेगी।

श्री रामेश्वर दत (नारनौंद): डिप्टी स्पीकर साहिब, आज बजट पर बहस होते हुए तीन दिन हो गये हैं। प्रत्येक सदस्य ने इसके ऊपर अनेक प्रकार की आलोचना करते हुए अपने अपने विचार रखें। बहुत से साथियों ने इस टैक्स को सही और जायज बतलाया लेकिन बाद में आकर यह मानना पड़ा कि यह टैक्स नाजायज है। मैं समझता हूं हमारे वित मंत्री महोदय बहुत पुराने,

योग्य और अनुभवी व्यक्ति हैं। लेकिन उनहोंने टैक्स लगाते समय शायद अपने साथियों से या अन्य सदस्यों से सलाह मश्विरा नहीं किया बल्कि किसी विशेष व्यक्ति के प्रभाव में आकर यह टैक्स लगा दिया हो। यदि ऐसा न होता तो जिमीदारों पर यह टैक्स न लगता। भारत ग्राम प्रधान देश है जिस में से हरियाणा के अन्दर 6990 गांव विद्यमान हैं। इन टैक्सों का सारा भार इन गांवों पर पड़ने से रोकिये। यदि पहले विचार किया जाता और हम पर यह टैक्स सोच–समझ कर लगाये जाते तो आज हाउस के अन्दर चारों तरफ यह आवाज न उठती और वित मंत्री महोदय ाके बाध्य होकर जो पानी का टैक्स वाविस लेना पड़ा है, वापिस नहीं लेना पड़ता। इसलिए यह गलती हाउस के अन्दर करना एक वित मंत्री द्वारा जो एक मान्य और अनुभवी व्यक्ति हैं, आज से नहीं पंजाब के समय से माने जाते हैं उनके लिए उचित नहीं।

वित मंत्रीः वह सैन्टर में देसाई साहिब भी कर रहे हैं।

श्री रामेश्वर दतः इस लिए सरकार से मेरा कहने का मतलब है कि आप सोचिये कि येटैक्स जितने भी लगे हैं नाजायज हैं और बगैर सोचे समझे और बगैर विचार करके लगाये हैं। आपने एक बार नहीं अनेक बार कहा कि आप आने विचार पेश करें, आप अपनी सलाह या मश्विरा दीजिए। आने कहा कि जमींदारों को छोड़ कर दूसरे 'साइड, पर टैक्स लगायें जिससे राज्य की आय बढ़े। लेकिन इसके विषय में अपना परामर्श पेश करूं इससे पहले मैं आपको यह बतला देना चाहता हूं कि इकसे अन्दर हर विषय

पर नजर डालें, दृष्टिपात करें और कहें कि अमूक अमूक विष्या के अन्दर इतना खर्च होगा। नहर के विषय की चर्चा हुई ब्यास, सतलूज, लिंक वगैरह का कहा। महेन्द्रगढ़ को भी उससे लाभ हुआ। हिसार जिला सारे हरियाणे का तीसरा हिस्सा है। सारे हरियाणा का तीसरा हिस्सा हो और जिसके बिजली और नहर के मिनिस्टर जिस जिले के हाहं उस जिले का जिक्र इस सारे वित मंत्री के भाषण के अन्दर हिसार जिले का नाम न हो। मुझे अफसोस और दुःख के साथ कहना पड़ता है यहां तक कि पानी पीने के लिए भी न हों। मेरे दोस्त और साथी जो लुहारू से आये हैं उन्होंने बतलाया कि पांच पांच, छः छः मील के अन्दर से ऊंटों पर पानी लाया जाता है। ऐसे इलाके का नहर के महकमे के विषय में कोई किसी प्रकार का वर्णन न करें तो हिसार के लिए सोतेली मां जैसा व्यवहार किया गया। तो इसलिए हमारे आज हिसार जिले के चार मिनिस्टर हैं उनको भी मैं यह सूचित कर देना चाहता हूं। उनका कर्तव्य उनके लिए क्या आवाज दे रहा है ? हिसार के रहने वालों! आपका कर्तव्य आपको पुकार रहा है। आप अपने जिले के एिल कोई अच्छा कदम उठायें। खैर वह उनकी इच्छा है। मैं उनसे यह भी आशा रखता हूं कि भूलें होती है। आइन्दा नहीं होगीं।

आपने शिक्षा के विषय में कहा। अब शिक्षा मंत्री महोदय तो चले गये लेकिन मैं उपाध्यक्ष महोदय के द्वारा यह सूचित करना चाहता हूं कि पांच सला के अन्दर सारे हाई स्कूल और मिडिल स्कूलों की जितनी संख्या सारे हरियाणा के अन्दर करनी थी। वह

अब तक 98 हाई स्कूल स्वीकृत कर चुके हैं, 112 प्राइमरी स्कूल मंजूर कर चुके हैं उसमें जब तीसरा हिस्सा जिला हिसार का है तो कम से कम 60 स्कूल हिसार जिले के अन्दर आते हैं लेकिन वहां अब जो हाई स्कूल और मिडिल स्कूल मन्जूर किये गये हैं। मुझे अफसोस तथा दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि उस हिसार जिले के 15.16 स्कूल मंजूर किये गये हैं।

(At this stage Sh. Mangal Sein, a Member of the Panel of Chairmen occupied the Chair)

मैं डाक्टर साहिब जिसको मैं उपाध्यक्ष, अध्यक्ष कहूं या चेयरमैन या हाउस का महान नेता या लीडर कहूं मुझे इसको देखकर बड़ी खुशी हुई, इसलिए चेयरमैन साहिब बहादुर के द्वारा मैं हाउस को यह निवेदन कर रहा था कि जो शिक्षा पद्धति इख्तियार की गयी है उसके अन्दर हिसार जिले के साथ अच्छा बर्ताव नहीं हुआ।

हिसार जिला जो शिक्षा में सब से पिछड़ा हुआ है जहां कि शिक्षा की बहुत कमी है जहां कि लोगों को यह नहीं पता कि स्कूलों के अन्दर पढ़ाया कैसे जाता है? इतना बड़ा जिला और वहां पर स्कूलों की इस प्रकार की हमारी सरकार वर्तमान गवर्नमैंट जो कि हमारे चेयरमैन के इशारे पर चलती है जो शिक्षा के बहुत हिमायती हैं उनको देख–रेख में हिसार जिले को इस प्रकार पीछे रखा जाये। मैं यह समझता हूं कि यह हमारे लिए शायद वे अपने हदय के अन्दर कोई स्थान नहीं रखते।

चेयरमैन साहिब से मैं यह निवेदन करूंगा कि हमारा यह प्रान्त, हरियाणा प्रदेश भाषा के आधार पर इसका निर्माण हुआ है। यदि हमारी भाषा का कोई किसी प्रकार विचार नहीं होता तो पंजाबी सूबा या हरियाणा प्रान्त नहीं बन सकता था। जब पंजाबी सूबे के अन्दर पंजाबी को वहां की प्रधान भाषा माना है। हरियाणा के अन्दर जिसके आधार पर बनने वाली जननी को जिसने इस प्रदेश को जन्म दिया उसके सपूतों ने उस पूज्य माता को ठुकरा दिया। आज हमारे शिक्षा मंत्री महोदय जो कि आज बहुत योग्य और लायक कहे जाते हैं हिन्दी में बोलना अपना अपमान समझते हैं, अंग्रेजी को ही अपनी मातृभाषा समझते हैं। मैं चेयरमैन महोदय से दरख्वास्त करूंगा कि आपने जंनसंघ का ध्येय अपना भारतीय प्राचीन संस्कृति का आधार रखा है।

चेयरमैन साहिब के द्वारा मैं इस चीज को शिक्षा के विभाग पर बोल रहा हूं। आपके द्वारा कि आप शिक्षा मंत्री महोदय तक पहुंचा दें आप उनको सूचित करें कि आप हिन्दी के अन्दर भाषण दिया करें। हाउस के प्रधान का यह कर्तव्य है और मेरा यह निवेदन है, मेरा अपना भी विचार है कि मैं समझता हूं कि तमाम हाउस के सदस्य इस चीज के लिए हमारे साथ सहमत होंगे। यह ठीक है कि हम अंग्रेजी को जानते भी हैं और उसका दर्जा रखना भी चाहते हैं लेकिन हमारे हाउस के अन्दर चाहे हम अंग्रेजी को बहुत ऊंची भाषा रखना चाहते हों लेकिन हमारे हरियाणा प्रान्त का मान है और नाम है आर प्रतिष्ठा को रखना हो तो हाउस में

हिन्दी में ही बोलना चाहिए क्योंकि हमारे आने वाले साथी जो कि हाउस की कार्यवाही को देखने के लिए आते हैं। वह अंग्रेजी नहीं समझ सकते। इसलिए मैं चेयरमैन साहिब आप से निवेदन करूंगा कि आप मेरे इन शब्दों की शिक्षा मंत्री महोदय के पास पहुंचा दे।

आगे नम्बर चौथा यह है कि हमारे वित मंत्री महोदय ने हरिजनों के लिए 70 लाख रूपया रखा है। हमें खुशी है इन्होंने जो कुछ किया है अच्छा किया है।

श्री सभापतिः आप अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री रामेश्वर दतः मैं तो आशा रखता था कि जब प्रधान जी बोलते हैं तो उनके लिए कोई सीमा नहीं होती इसलिए मेरे लिए भी खुला समय होगा ताकि मैं सब बातें कह सकूं।

श्री सभापतिः मैं तो टाईम के अनुसार ही बोलता हूं।

श्री रामेश्वर दतः मैं निवेदन कर रहा था हरिजनों के लिए जो 70 लाख रूपया दिया गया है यह अच्छी बात है, इससे पहले भी बहुत सा रूपया उनके लिए रखा जाता था। लेकिन मुझे खेद से कहना पड़ता है कि उनके कारोबार, रिहायश और हालत को देखें तो उसमें कोई सुधर नहीं दिखाई देता। इस का मतलब है कि कहीं पर कोई कमी है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि उनकी हालत को सुधारा जाए। हमारे वित मंत्री महोदय ने अपनी बजट स्पीच में कहीं पर जिक्र नहीं किया कि बैकवर्ड जातियों के लिए भी कुछ किया जाएगा। उनको बिलकुल नजरअंदाज किया

गया है। मैं प्रार्थना करूंगा कि उन की तरफ ध्यान दिया जाए। बातें तो बहुत सी और भी कहनी थीं लेकिन समय नहीं। इसलिए मैं अपना स्थान लेता हूं।

श्रीमति स्नेह लता (हिसार): चेयरमैन साहिब हरियाणे के बजट में विशेषता है इसने रिकार्ड कायम किया है। पहला रिकार्ड तो यह है कि इन्होंने सात टैक्स लगाए हैं जिसकी कि आप को कहीं पर भी मिसाल नहीं मिलेगी। दूसरा रिकार्ड यह है कि इनका डैफिसिट बजट है जो कि असल में 13 करोड़ रूपए के करीब है। इस की भी मिसाल आप को नहीं मिलेगी। तीसरा रिकार्ड यह है कि मंत्रियों की फौज कायम कर दी गई है। सात जिलों की स्टेट में 18 मंत्री तो इस वक्त हैं और कल परसों के ट्रिब्यून अखबार में था कि दो मंत्री और बन जाएंगे।

मुख्य संसदीय सचिव: 13 दिनों में आपका तख्ता उलटा दिया, यह भी एक रिकार्ड।

श्रीमती स्नेह लता: बगग्र प्वायंट आफ आर्डर के ही आप इण्ट्रस्ट कर हे हैं। यह कैसा तरीका है। चेयरमैन साहिब पार्टीशन से पहले जुआइंट पंजाब में 29 जिले थे और पांच मिनिस्टर हुआ करते थे। इस वक्त जब हमारी इकानोमी इतीन कमजोर है आपने 8 मन्त्री बना रखे हैं।

वित्तमंत्री: 1 नवम्बर,1956 को कितने थे।

श्रीमती स्नेहलता: वह भी गलत थे। चेयरमैन साहिब अगर इनको मिनिस्टरी का इतना डर है तो यह हरेक को मिनिस्टर बना दें और एक एक मिनिस्टर के साथ चार डिप्टी मिनिस्टर लगा दें ओर इनकी सीनीयारेटी का फैसला करने के लिए हाउस का एक कमीशन बना दिया जाये ताकि इनका झगड़ा न हो और इनको मिनिस्ट्री के टूटने का कोइ खदशा न रहे। चेयरमैन साहिब जिस बेरहमी के साथ जनता का पैसा मिनिस्टरों की फौज पर जाया किया जा रहा है लोग इसे हरगिज पसंद नही करते।

आज मैं इकोनोमी करने के लिए कुछ सुजैशनज देना चाहती हूं। पहला तो यह है कि डी.पी.आई आफिस और सैक्रेटरी आफिस को एमलगामेट कर दिया जाए क्योंकि यह महज डुपलीकेशन है ओर उनकी ऐफोशैसी बिलकुल जीरो है। जब 29 जिलों के पंजाब में एक डी.पी.आइ काम कर सकता था तो कोई वजह नहीं कि अब सात जिलों के सूबे में एक अफसर काम न कर सके। अगली सुजैशन यह है कि जो सिनेमा की सीटों पर टैक्स बढ़ाया है वह सिर्फ अकपाइड सीटों पर होना चाहिए क्योकि इससे छोटे–छोटे सिनेमाज पर भी असर पड़ेगा ओर वह लोग चला नहीं सकेंगे। हम तो चाहते है कि टैक्स लगे लेकिन यह नहीं कि अन्धा धुंध लगा दिया जाए। बस मैं इतना कह कर बैठती हूं।

ग्राम्य विद्युतीकरण राज्यमंत्री: (मेजर अमीर सिंह) : चेयरमैन साहिब मैं बोलने वालों में नहीं था लेकिन एक दो बातें कही गई है उनका जवाब देना लाजमी समझता हूं क्योंकि उनके

साथ मेरा ताल्लुक है। मैं दो तीन दिनों से सुनता आ रहा हूं जो भी उठता है वह सरकार के खिलाफ या टैक्सों के खिलाफ ही बातें करता रहा। मैं इस बात को बुरा नहीं मानता क्योंकि इन बेचारों का 22 साल का राज अब हाथ से चला गया है तो फिर यह क्यों न कहे कि कुरप्शन है। 1000 साल इनको कुरप्शन दूरन करने का खयाल नहीं आया मैं मानता हूं कुरप्शन है लेकिन इसका कौन जिम्मेदार है। जितीन नुक्तानीनी इन्होंने की, इन्होने यह नहीं सोचा कि यह हमारे ऊपर ही आती है। यह तो बेरंग चिट्ठी है, अगले ने न ली तो इनके पास वापिस आएगी। तो यह सारी इनकी अपनी की हुई बातें हैं। मैं इस बात से इन्कार नहीं करता कि मै। भी इनके अन्दर ही था (शोर) लेकिन मैं ने जब इनका रंगा ढंग देखा तो भागा ..... शोर ..... मैं इनकी सब बातें जानता हूं और मैं समझता हू कि इनके डबने का कारण भी यही है कि इन्होंने समझ लिया कि यह इनकी गदियों है और हमेशा इनके हाथ ही रहनी चाहिएबड़े जोर शोर से कहा गया कि साहिब बड़ी कुरप्शन है हर जगह कुरप्शन हो कुरप्शन नजर आती है और कुछ नजर नहीं आता लेकिन देखने वाली बात तो यह है आखिर इसके लिए कौन जिम्मेदार है? यह संयुक्त दल जिम्मेदार है या पिछली सरकार। क्या यह कुरप्शन अब दो महीनों से ही नजर आने लग पड़ी और पहले यह लोग क्या करते रहे? जहां तक मेरे महकमों का ताल्लुक है मैं सबको दावत देता हूं कि मैं सुबह से शाम तब दफ्तर में बैठा रहात हूं ओर यह सुधार के कामों में ही लगा रहता हूं आप मेरे पास आएं बताएं और कोई केस हो मेरे नोटिस में

लाएं एक घंटा के अन्दर अन्दर कार्यवाही होगी। मैं मानता हूं कि सटाफ ज्यादा है और मैं यह भी मानता हूं कि अफसर भी बड़े हैं। पुलिस को ही आप ल`ले पहले एक डी.आई.जी होता था लेकिन अब एक दर्जन से कम क्या होंगे लेकिन मैं इनसे कहता हूं कि जब तकसीम होने लेगी थी तो आपने इन्कार कर देता था कि हमें इतने आदमियों की जरूरत नहीं। यही हाल हर एक महकमा में है एक महकमा की ही बात क्यों करूं। पैप्सू के पांच जिले होते थे और पी.डब्लयू.डी. का एक चीफ इन्जीनियर होता था लेकिन अब एक दर्जन चीफ इन्जीनियर हैं। मैं यह बात मानता हूं कि वह बहुत काबिल आदमी हैं लेकिन जब हमारे घर में कोई गुंजायश न हो तो हमउ न काबिल आदमियों को रखेंगे कहां? जब बटवारा हुआ तो आपने क्यों इतने आदमी लेने मान लिए और आज हमें किस मुह से कहते हो कि ज्यादा आदमी हैं, करें आप और भरें हम, यह कहां की दलील है। एक चौधरी धर्मपाल सिंह जी हैं जो सी.सी. ऐफ. ह ैअब आप देखें कि जंगलात तो दे दिए हिमाचल प्रदेश की और धर्मपाल जी हमें दे दिए ..... शोर .....

श्री सभापति: आप किसी अफसर का नाम न लें।

ग्राम्य विद्युतीकरण राज्यमंत्री: चौधरी धर्मपाल सिंह जो बहुत काबिल आदमी है और बहुत लायक हैं लेकिन मैं जो बात कह रहा हूं वह यह है कि जब यह बटवारा हुआ तो इन्होने यह कैस मान लिया कि जंगलात तो जाएं किसी और को और स्टाफ आए हमारे घर को .....

श्रीमती ओम प्रभा जैन: वजीर साहिब बड़े जिम्मेदार आदमी हैं उन्हें पता होना चाहिए कि जिस वक्त असैट्स ऐड लाएबिल्टी बांटी गई उस वक्त गवर्नर साहब की हकूमत थी हम नहीं थे।

राज्यमंत्री: मैं मानता हूं कि उस वक्त गवर्नर साहिब थे और आपकी हकूमत नहीं थी लेकिन मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपकी हकूमत आई तो क्या आपने प्रोटैस्ट किया इसके खिलाफ? यह कयाबात हुई कि हिमाचल वालों ने जंगलात तो ले लिए लेकिन सी.सी.ऐफ. साहिब को लेने से इन्कार कर दिया। फिर आप देखें एक आई.जी. है बड़े सीनियर मोस्ट आदमी हैं पंजाब वालों ने लेने से इन्कार कर दिया और फिर बारडर पुलिस में लगाया गया फिर एक सीनियर मोस्ट डी.आई.जी. बैठा है लेकिन उसे आई. जी. बनाने से इन्कार कर दिया। आपको प्रोटैस्ट करना चाहिए था इन सारी बातों पर लेकिन चुप बैठे रहे। मैं कहता हूं कि आप कहे या न कहें हम आहिस्ता आहिस्ता लगे हुए हैं इसे ठीक करने के यत्न कर रहे है लेकिन हमें जादू तो आता नहीं कि बीस साल का आपका गंद साफ कर दें मगर आप हमें टाइम ही नहीं देते हमारी टांगे खींच रहे हैं। जो आप कोई तामीरी–नुकताचीनी करे हम वैलकम करेंगे लेकिन हमें इस जोड़ तोड़ से दम मिले। अगर आप इसी तरह जोड़ तोड़ में लगे रहे तो न तो हरियाणा की कोई तरक्की होगी और न जनता का भला होगा ओर हम भी इस जोड़ तोड़ से यह सरकार नहीं जाने देंगे जो लगा लो। आज यह इतनी

वजीरों को बारात क्यों है? इसका भी कारण है। यह आपके जोड़ तोड़ का मुकाबला करने के लिए है। अगर आप हमारी टांग खींचेगे तो हम ओर मजबूती के साथ बैठेंगे आपकी टांग नहीं खींचगे देंगे। तो यह बारात बनाने के लिए आप लोग जिम्मेदार हैं और कोई नहीं। फिर यही एक बारात नहीं इससे भी बड़ी बड़ी बारातें बनी हैं लेकिन हम तो यह बारात छोटी करने के लिए तैयार हैं हम आज कर देते हैं मगर यह नहीं होने देंगे कि आप हमारी टांग खींच कर हमें गिराने को बातें करें और हम चुप बैठे रहें। ऐबरी थिंग इन फेयर इन लव ऐंड वार इसलिए अगर आपको यह लड़ाई चलेगी तो हमें भी आपका मुकाबला करने के लिए हर तरह की टैकटिक्स इस्तेमाल करने पडेंगे न राज आपने अपनी मर्जी से छोड़ा और न हम हो छोडेंगे। हां जबरदस्ती आप छुड़ा लें तो हम लाचार हैं। चेयरमैन साहिब मैं आपका ज्यादा वक्त न लेता हुआ यह कहना चाहता हूं कि मेर पास दो महकम टाप कुरप्ट हैं लेकिन यह कह देना कि सारे के सारे कुरप्ट हैं गलत बात है ईमानदार भी हैं और बेइमान भी हैं दोनों किसम के हैं। जो खराब है। उन्हें ठीक करने में मेरी तवज्जुह लगी हुई है। आप आएं और मुझे कोई केस बताएं किसी को पकडाएं अगर मैं उसे घंटे के अन्दर अन्दर जंगले के पीछे न रख दूं तो मुझे कहना। ऐसे ही खाली बातें करने से तो कोई बात नहीं बनती है। इन शब्दों के साथ मैं फिनांस मिनिस्टर साहिब को मुबारिकबाद देता हूं कि उन्होंने ऐसा बजट पेश किया है कि उन्होंने हर चीज को बड़े

मुनासिब ढंग से बैलेंस में रखने की कोशिश की है और इस पर किसी किस्म की नुकताचीनी करना नामुनासिब है।

चौधरी शिव राम वर्मा (नीलोखेड़ी): चेयरमैन साहिब, आज तीन दिन से इस बजट पर बहस हो रही है और इस पर काफी विचार हुआ है। मैं समझता हू कि जैसा बजट इस दफा जिस सूझबूझ और मेहनत से तैयार किया गया और पेश किया गया है आजतक पिछले 18/20 साल से कांग्रेस सरकार कभी ऐसा बजट पेश नहीं कर सकी (शोर) यह जो कांग्रसी भाई तड़पते हैं इसका एक कारण यह भी है कि इनके मन में वही बात है जिस तरह पहले भी कहा जा चुका है कि यह तो पिछली सरकार का बच्चा है और पालना इस सरकार को पड़ गया है ओर उनको तड़प इस बात की है कि कहीं यह न हो कि उनके बच्चे को यह पाल न सकें लेकिन वित्तमंत्री ने जिस तरह उस बच्चे को सजा संवार कर सदन के सामने पेश किया है और पेश करने का प्रयत्न किया है उससे उनको तसल्ली हो जानी चाहिए और उनकी यह तड़प कि शायद उनका बच्चा वह न पाल सकें खतम हो जानी चाहिए। मैं समझता हूं कि वित्तमंत्री महोदय ने जो पिछले बजट में सुधार किया है वह जनता की भावनाओं के अनुसार है और सदन के सदस्यों के विचार के अनुसार है। जो कुछ बातें ऐसी की गई थीं जिनके बारे में जनता और सदन ने महसूस किया था कि यह जनता पर बोझ होगा उन्हें इस सरकार ने सयुक्त दल की मीटिंग में फैसला करने के बाद ड्राप कर दिया। जो आबियाना बढ़ा था

उसे वापस लेकर उन्होने बड़ी सूझबूझ और समझदारी का सबूत दिया है लेकिन फिर भी यह हमारे कांग्रेसी भाई इन बातों को बार बार उछालते हैं। उनको देखना चाहिए कि इसमें कितनी अच्छी अच्छी चीजें हैं और कितनी अच्छी बातें की गई हैं। जो सुधार यह 15–20 साल में नही

10.00 a.m.

कर सके वह ये चाहते है कि एक दिन के अन्दर हो जाए। भला वह एक दिन के अन्दर कैसे हो सकता है? इन्होंने मलबे का जो ढेर 20 सालों में इकट्ठा किया है वह एक दिन में साफ करना बड़ा मुश्किल है। काफी वक्त लगेगा। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा इस सदन का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि जितना काम पिछली सरकार 20 साल के लम्बे अर्से में नहीं कर सकी उसको इस सरकार ने दो महीने के अर्से में ही कर दिया। फिर आगे के लिये भी जो कांग्रेस सरकार का काम था, उसे भी यह सरकार जल्दी कर रही है। उदाहरण के लिये स्कूल अपग्रेड करने का जो प्रोग्राम कांग्रेस सरकार ने पांच सालों के लिये बनाया था उसे इस सरकार ने इसी साल के अन्दर अन्दर पूरा करने का जिम्मा लिया है। यह एक बड़ा भारी कदम है। जिस कौम में एजूकेशन का प्रचार बढ़ेा, वह कौम कुदरती बात है कि आगे बढ़ेगी। अध्यक्ष महेादय, कांग्रेस सरकार तो चाहती थी कि लोग अनपढ़ बने रहे ताकि इनकी गलत फलत पौलिसियां चलती रहे और इनको वोट मिलते रहे। लेकिन इस सरकार ने सोचा कि

शिक्षा का प्रसार होना चाहिए। कांग्रेस सरकार ने योजना बनाई थी कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कोई 250 प्राइमरी स्कूल मिडल स्कूल बनाए जायेंगे लेकिन इस सरकार ने पहले साल में ही 110 प्राइमरी स्कूल मिडल स्कूल बना दिये हैं। इसी तरह कांग्रेस से ज्यादा मिउल स्कूलों को हाई स्कूलों में परिवर्तित किया जाएगा।

श्री औम प्रकाश शर्मा: ओन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। जिस तरह से स्कूल एक साल में बढ़ा दिये गये, क्या इसी तरह सड़कें भी बढ़ा देंगे।

श्री सभापतिः यह कोई प्वायंट आफ आर्डर नहीं है। यू ही क्यों रोकते हो इनको।

चौ. शिव राम वर्मा: पिछली सरकार ने पांच सालों में 110 मिडल स्कूल हाई और हायर सैकंडरी स्कूल बनाने थे मगर इस संयुक्तदल की सरकार ने पहले साल में ही 98 स्कूलों को मिडल से हाई या हायर सैकंडरी स्कूल बना यिदा। तो मैं समझता हूं कि इस सरकार ने इस थोडे से अस्रे में ही बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन इतने बड़े कदम उठाने के बाद भी यदि कांग्रेस नुक्ताचीनी करे तो मैं समझता हूं कि वह जायज नहीं और दिल में वे भी समझते है कि काम तो इस दल की सरकार ने किया है परन्तु यदि वह यह बात कहने लग जाय तो जनता को मुंह नहीं दिखा सकते। इस लिये वे यहां शोर मचाने की कोशिश करते हैं।

ताकि कुछ जवाब तो बाहर जाकर उनके पास हो ओर वे कह सकें कि हमने तुम्हारे लिये वहां यह कहा और वह कहा।

पीने के पानी के बारे में जो कमी काफी इलाकों में रहती रही है और जिसको कांग्रेस 20 साल के राज में पूरा नहीं कर सकी इस बजट के अनदर काफी हद तक दूर करने की कोशिश की गई है। परन्तु इस तरफ और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। इसी तरह आयुवैदिक डिसपैसरियां खोलने के बारे में जितना ध्यान इस सरकार ने बहुत थोडे समय में दिया है उतना कांग्रेस ने जो कि अभी भी शासन के लिये तड़पती है 20 साल में नहीं दिया । इन बातों के मुकाबला करने से पता लगता है कि यह बजट कितना अच्छा है और कितना लाभदायक सिद्ध हो सकता है। मैंने पहले भी बात कही कि कांग्रेस वालों ने जो मलबा, कूड़ा कर्कट 20 सालों में इकट्ठा किया है उसे साफ करने में कुछ समय लगेगा। चेयरमैन महोदय, इस सम्बन्ध में मैं एक मिसाल देना चाहता हूं। कोई गाना सीखने के लिये एक गायक के पास गया और कहने लगा कि मैं आप को गुरू मानकर आया हूं और आपसे गाना सीखना चाहता हूं। मुझे आशा है कि आप सिखायेंगे। उसने कहा कि जरूर सिखाऊंगा। उसने पूदा कि कितना अर्सा लगेगा। उसने विचार कर कहा कि 2 साल तो कम से कम लगेंगे। तो उसने घबराकर कहा कि दो साल तो बहुत ज्यादा हैं। क्या इससे कम नहीं लग सकते क्योंकि मैं गाना थोड़ा बहुत पहले भी जानता हूं। आचार्य ने उत्तर दिया कि तब तो आपको 4 साल लगेंगे।

गाना सीखने वाले ने पूछा कि 4 साल क्यों लगेंगे? गायक ने उत्तर दिया कि दो साल तो आपके गले से गलत स्वर को उतारने में लगेंगे? गायक ने उत्तर दिया कि दो साल तो आपके गले से गलत स्वर को उतारने में लगेंगे और दो साल सही स्वर को चढाने में लगेंगे। तो इसी तरह से, चेयरमैन महोदय, कांग्रेस शासन द्वारा 20 साल में किये गये गलत कामों को ठीक करने के लिये बहुत ज्यादा अर्सा चाहिए। मुझे विश्वास है कि संयुक्त दल की सरकार उनको इन पांच सालों में ऐसा कर देंगे कि लोग महसूस करेंगे कि वाकई काम बहुत तेजी से चल रहा है और लोगों को तसल्ली होगी कि यह कुछ करना चाहते हैं।

इस तरह से मैं एग्रीकल्चर की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहूंगा कि इस कांग्रेस की पिछली 20 साल की सरकार ने कुछ नहीं किया लेकिन इस बजट का मुकाबला अगर ये करें तो एक साल के बजट में हम उनको कहां लाकर छोड़ते है। यह ब्यान देने की जरूरत है। इतना ब्यान दिया गया है कि जमुना पर भी कांग्रेस नहीं रही। वह जमुना पर से भी भाग चुकी है। एग्रीकल्चर की तरफ जितना ध्यान देने की जरूरत थी अगर वह दे दिया जाता तो मैं समझता हूं कि यह अन्न संकट खड़ा नहीं होता लेकिन इस कांग्रेस सरकार का ध्यान तो एक ही तरफ था कि लोग भूखें रहें, अनपढ़ रहे ताकि इनको वोट मिलते रहें और इनका राज चलता रहे। लेकिन काठ की हंडिया बार कार नहीं चढती और जिसका नतीजा यह है कि आज आधे से ज्यादा देश में कांग्रेस खदेड़ दी

गई है जिसका कि इन्हें निहायत अफसोस है और उन अयाशियों की जिन्हें ये किया करते थे उन्हें रह रह कर याद आती रहती है। तो मैं अपने साथियों से निवेदन करूंगा कि वे इस बजट को अच्छी तरह से यदि पडेंगे तो उन्हें पता लगेगा कि कितना काम बहुत जल्दी ही होने वाला है।

यहां एक सुझाव आया इकोनोमी के बारे में। यह मैं समझता हूं कि दफतरों में कई लाइन्ज बनी हुई हैं। लेकिन इसमें इस सरकार का कोई दोष नहीं। वे तो पहले से ही बनी हुई हैं। (अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए) मगर, फिर भी मैं इस सरकार का ध्यान उस तरफ दिलाना चाहता हूं। हर तरफ दो दो तीन तीन लाईनें बना दी गई हैं। जैसे डायरैक्टर, डिप्टी डायरैक्टर और असिस्टेंट डायरैक्टर। कमिश्नर, डवैल्पमैंट कमिश्नर, प्रोडक्शन कमिश्नर, डिविजनल कमिश्नर। सैक्रेटरी, डिप्टी सैक्रेटरी, असिसटैण्ट सैक्रेटरी। इसी तरह से और कई लाइनें चलती हैं। जब यह प्रान्त केवल एक डिविजन का प्रान्त रहा गया है तो इस तरफ ध्यान देने की जरूरत है। यदि इस तरफ ध्यान दिया गया तो काफी बचत सरकार को हो सकती है।

मैं कुछ उद्योग–धंधों की तरफ भी ध्यान दिलाना चाहता हूं। हरियणा प्रान्त इंडस्ट्री के लिहाज से बहुत पीछे है। उद्योग धन्धों की तरक्की के लिये बहुत तेजी से चलने की जरूरत है, इसलिये मैं सरकार से दरखास्त करता हूं कि इस और खास ध्यान दें।

एक बात खास तौर पर सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं। जो बड़ें बड़े लखपति और करोड़पति हैं, जो पता नहीं किन किन गलत ढंगों से रूपया कमाते हैं, उनकी रोकथाम के लिये सरकार कदम उठाए। वह जगह जगह बड़े बड़े फार्म खरीद लेते हैं और खेती शुरू कर देते हैं। उन फार्मो में जितनी एक्चुअल पैदावार होती है उसको सही सही नहीं बताते। इस तरह से वे इस ब्लैक मनी को छुपाने के लिये जगह जगह भागते फिरते हैं। पैदावार को कभी कम बता देते हैं ओर कभी ज्यादा। यहां दस मन अनाज होता हे उसको पचास मन दिखाने की कोशिश करते हैं इस तरह से लाखों रूप्यें की बलैक मनी होती हैै। इसलिये सरकार को इस ब्लैक मनी को रोकना चाहिए। जो गरीब किसानों पर टैक्स लगाया गया है वह इन सरमायेदारों ओर बड़े जमींदारों पर लगाया जाना चाहिये।

स्पीकर साहिब, सड़को के बारे में मेरे भाईयों ने जिक्र किया कि इसमें भी तरक्की होनी चाहिए। ठीक है। इस तरफ भी तेजी से ध्यान देना चाहिये, लेकिन एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा और वह यह है कि एक मील लम्बी सड़क पर साठ–अस्सी हजार रूपया खर्च आता है। यह इतनी बड़ी रकम होने की वजह से शायद तेजी से काम न चल सके, लेकिन फिर भी मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इस तरफ विशेष ब्यान दिया जाए। हरियाणा प्रान्त के अन्दर वैसे ही सड़कों की कमी है। कुछ इलाकें ऐसे है जहां कई मील पैदल चल कर सड़क आती है। इसके बाद

सड़कों के बारे में दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि जो गांव वालों से 25 फीसदी रूपया देने की तजवीज हुई थी और वह मंजूर भी हो चुकी थी लेकिन कई जगह उन सड़कों पर काम शुरू नहीं हुआ है। अगर कहीं काम शुरू हुआ भी है वह कुछ दिन बाद बन्द हो गया। इसके बारे में कांग्रेस बैंचिज की तरफ से भी कई सवाल पूछे गये कि कई जगह काम शुरू नहीं हुआ है। अगर कहीं काम शुरू हुआ भी है वह कुछ दिन बाद बन्द हो गया। इसके बारे में कांग्रेंस बैंचिज की तरफ से भी कई सवाल पूछे गये कि कई जगह काम शुरू हुए और कुछ दिनों के अन्दर बन्द हो गये। लेकिन मैं बता देना चाहता हूं कि इसका सरकार के साथ कोई ताल्लुक नहीं, यह अपने साथियों से पूछें कि क्यों बन्द हुआ। वे इसका कारण अच्छी तरह से समझते हैं (घंटी)। स्पीकर साहिब मैं थोड़ा सा एग्रीकल्चर एजूकेशन के बारे में निवेदन करता चाहता हूं। आज एग्रीकल्चार एजूकेशन की बड़ी आवश्यकता है .....

श्री अध्यक्ष: देखिए मेरे पास टाईम बहुत थोड़ा है, आपको बोलते हुए 18 मिनट हो गये हैं।

चौ. शिव राम वर्मा: मैं दो तीन मिनट में ही खतम करता हूं। करनाल में एक एग्रीकल्चार कालेज है, उसकी प्रगति के लिये सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। पिछली बार जो गवर्नर एड्रैस था उसमें इसका जिक्र था लेकिन इस बार इसे इग्नोर कर दिया गया, इसके लिये सरकार कुछ न कुछ करे।

इसके इलावा दूसरी बात यह है कि पहेवा के इलाके में दूसरे प्रान्तों के लोगों को गलत तरीके से ठेके दिये जाते हैं। पहले ठेके साल साल के लिये दिये जाते थे लकिन अब 20 साल के लिये कर दिये हैं। पंजाब के लोग वहां आबाद कर दिये और हरियाणा के लोगों को इग्नोर किया जाता है। इसमें भी एक साजिश काम करती थी। मैं आशा करता हूं इसकी ओर सरकार ध्यान देगी। इन शब्दों के साथ में बजट का समर्थन करता हूं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा (थानेसर): स्पीकर साहिब, जब से बजट विधानसभा में पेश हुआ है, इसके सम्बन्ध मं तरह तरह की बातें चल रही हैं। कुछ भाईयों द्वारा यह कहा गया कि यह पापुलर गवर्नमेंट का पापुलर बजट है और कुछ भाईयों ने अन–पापुलर गवर्नमेंट का अन–पापुलर बजट कहा। इससे यह साफ हो गया कि बजट या पापुलर है या अनपापुलर। इसके लिए थोडा सा मैं अर्ज करना चाहता हूं कि जो टैक्सज इस गवर्नमेंट ने लगाये, वह आपके सामने हैं। जैसा कि आब्याना टैक्स सजीद लगाया गया और उसको दुगना कर दिया गया था उसको माफ करवाने के लिए मैं अपने अपोजीशन भाईयों को मुबारकबाद देता हूं और रूलिंग पार्टी के भाईयों को भी मुबारिकबाद देता हूं जिन्होंने आपोजीशन पार्टी का इस काम को करने में साथ दिया। मै। रूलिंग पार्टी से उम्मीद करता हूं कि वे अपनी कुर्सी का ध्यान न रखते हुए, इस प्रकार के टैक्सों से जनता को बचाने के लिए आपोजीशन का

साथ देंगे। स्पीकर साहिब जो आब्याना टैक्स वापिस लिया, इसके लिए मैं वित्तमंत्री को बहुत बहुत मुबारिकबाद देता हूं।

इसके इलावा दूसरी बात यह है कि जमींदारों को टयूबवैल्ज के कुनैक्शन देने के लिए उन्हें बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। दो दो तीन तीन सालो ंसे कुनैक्शन नही मिले। टैस्ट रिपोर्ट दी हुई है लेकिन इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसके इलावा जमींदारों में एक और बीमारी पैदा कर दी गई है। इसके इलावा जमीदारों में एक और बीमारी पैदा कर दी गई है। बिजली लगाने क लिए जमींदारों से खम्भे मांगे जाते है। पीकर साहिब, एक जमीदार को हजार हजार रूपए के खम्भे देने पड़ते हैं और तब कहीं जाकर बिजली का कुनैक्शन मिलता है। मेरा कहने का मतलब यह है कि जब तक आप जमींदारों को ऊपर नहीं उठोयेंगे तब तक यह मसला हल नहीं हो सकता। रिश्वत लेने से देश का भला नहीं होगा। जिस तरीके से मिनिस्टर रिश्वत ले रहे हैं और जिस रेशो से समग्लिंग हो रही, उससे आप देंखेंगे कि ..... (इंट्रप्शन)

श्री राम पाल सिंह: स्पीकर साहिब, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई मेम्बर किसी दसरे मैम्ब्र पर इस प्रकार एसपर्शन कास्ट कर सकता है कि ये समग्लिंग कर रहे हैं? ये शब्द विदड्रा होने चाहियें। नहीं तो वे इसको साबित करें। (इंट्रप्शन)

श्री अध्यक्ष: आप इन शब्दों को विदड्रा कर लें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: चलो मैं वापिस लेना हूं। हां, मैं कह रहा हूं कि जिनको मिनिस्टर नहीं बनाया गया उन्हें कुछ इलाके दिए गए हैं। एक बात मैं जनसंघ के लीडर डा. मंगल सैन के बारे में कहना चाहता हूं। इनके लिए आप जगह रख ले क्योंकि अगर समग्लिंग चलती रही तो वे इसमें से गुजर नहीं सकेंगे .....

श्री अध्यक्ष: यहां हाउस में कुरप्शन का बड़ा जिक्र चल रहा है इसको बन्द करें .....(इंट्रप्शन)

श्री ओम प्रकाश शर्मा: स्पीकर साहिब, इनके इलावा पटवारी रिश्वत लेते हैं, सिविल सप्लाई डिपार्टमेंट वाले रिश्वत लेते हैं और कई जगह रिश्वत लेते हैं। लेकिन मेरी गुजारिश यह है कि जब तक कुरप्शन बड़े लैवल पर खतम नहीं होती तो ओर जगह पर कैसे खतम हो सकती है। हमारे अपोजीशन बेंचिज की तरफ से कई साथी मिनिस्टरों के लालच में आकर इधर से उधर जा बैठे हैं यह कुरप्शन नहीं तो और क्या है.....

श्री अध्यक्ष: यह काबले इतराज बात है, ऐसी बाते न कहें।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: जनाब स्पीकर साहिब, आज कल कलकत्ते मं क्या हो रहा है, यह सब को पता है। ऐसे वक्त में हमें सोचना होगा कि क्या होना चाहिए। मान लिया कि काग्रेस के राज्य में धांधली होती, रही, लेकिन मैं यह पूछना चाहता हूं अपने दोस्तों से कि आखिर धांधली करने वाले कौन थे जो धांधली

करने वाले कांग्रेस में मौजूद थे, वही अब संयुक्त दल में जा पहुंचे हैं। तो फर्क क्या पड़ा। जनाब जनसंघी भाई जनता की सेवा करने के लिए अपनी मौनोपली समझते हैं, लकिन प्रोपर्टी टैक्स के वक्त किसी जनसंघी ने यह नहीं सोचा कि प्रापर्टी टैक्स क्यों लगा है। क्या किया जनसंघी भाई ने प्रोपर्टी टैक्स की बात उठाई? (घंटी)

श्री अध्यक्ष: आप अब वाइंडअप कीजिए।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: जनाब, मैं एक बात मालगुजारी के बारे में कहना चाहता हूं। मालगुजारी अब पहले से डेढ गुनी कर दी गई है, इस पर मुझे एतराज है। कुछ जमीनें ऐसी हैं जो बेकार पड़ी हैं और इस तरह पहले की मालगुजारी भी जायज नहीं है तो नई मालगुजारी का बढाया जाना कहां तक जायज है, यह हटाई जानी चाहिए। (घंटी) स्पीकर साहिब, पेपर मिल्ज को गवर्नमेंट आफ इंडिया ने भूसा खरीदने की इजाजत दे दी है। इसका नतीजा यह हुआ है कि हरियाणा के अन्दर उन मिल वालों ने लाखों मन भूसा स्टोर करके पैपर बनाने के लिए रख लिया, जिससे चारे की और भी कमी हो गई है। इसके लिए सरकार कदम उठाए और भूसे की खरीद को बन्द करें।

श्री राम किशन आजाद (एस.सी.जुण्डला): स्पीकर साहिब, मैं एक मिनट लेकर अपनी बात खतम कर दूंगा। मैं तो सिर्फ यही कहना चाहता हूं कि सरकार ने सरकारी मुलाजमों की मांगों को मदेनजर रखते हुए उनको कुछ डी.ए. वगैरा देने का

फैसला किया, लेंकिन उससे कर्मचारियों को पूरा फायदा नहीं हुआ। इस पर जो पाबन्दी लगाई गई है, मेरी राय है कि वह हइा देनी चाहिए और उन्हें पूरा डी.ए. देना चाहिए। इसके साथ ही मै। हाउस के अन्दर एक ऐसे मजदूर और कर्मचारी की बात कहना जरूरी समझता हूं जो कि सोसायटी का एक अहम अंग है, वह जितनी भी सोसायटी की गंदगी होती है उसको साफ करता है। उनके बारे में इस बजट में कुछ जिक्र नहीं आया। जो तन्खाहें बड़ी हैं, वह सरकारी कर्मचारियों की बढ़ी हैं, लेकिन जो सफाई मजदूर है जो शहर में काम करता है या देहात में काम करता है उसके लिए कुछ भी नहीं सोचा गया जबकि वह भी उसी महंगाई का शिकार है जैसा कि और लोग। मैं सरकार ने निवेदन करना चाहता हूं कि इन सफाई मजदूरों की तन्खाहें बढ़ाने के बारे में किसी ने किसी प्रकार कदम उठाया जाये ताकि उनको भी इस मंहगाई के जमाने में सहूलियत मिल सके। लेकिन वहां की लोकल बाडीज और जनसंघ पार्टी जो वहां की हुक्मरान है वह कहते हैं कि हमारे लिये सरकार का हुक्म कोई हुक्म नहीं है। मैं निवेदन करूंगा कि इस देश के मजदूर की मेहनत को मदेनजर रखते हुए आप उनको हुक्म दे कि वह उनके पैसे बढ़ाएं। अगर ऐसा न हुआ तो वह एजीटेशन करेंगे। जिससे प्रदेश मैं लोगों की सेहत पर असर पडेगा। बजाए इसके कि झगड़ा बढ़े सरकार पहले ही उसको ठीक कर दे।

श्री अध्यक्ष: अब आप बैठ जायें।

वित्तमंत्री (श्रीमूल चन्द जैन): स्पीकर साहिब, हरियाणें के पहले बजट पर तीन दिन से इस मुअजिज इवान में बहस हो रही हैं यह बजट हरियाणे स्टेट का पहला बजट है। बजट किसी स्टेट का हो या सारे मुल्क का हो वह उस स्टेट के या उस देश के लोगों की तमन्नाओं या उमंगो का प्रतीक होता है। पेशतर इसके कि मैं इस बजट पर की हुई बहस के मुख्तिलिफ पहलुओं पर रोशनी डालूं मैं आपके द्वारा कहना चाहता हूं कि बड़ी मुदतो ंके बाद, मकरीबन 100 साल से भी पहले से हरियाणे के लोग इस बात की बार बार उम्मीद करते थे कि कभी वक्त आएगा हरियाणा अलग स्टेट बनेगी और फिर हम अपनी स्टेट के लोगों की भलाई के काम हम अपनी मर्जी से कर सकेंगे। स्पीकर साहिब आप मुझसे भी ज्यादा जानते हैं कि सन् 1857 में जब अंग्रेज के खिलाफ आजादी की पहली जंग हिन्दुस्तान के लोगों ने लड़ी तो उसमें हरियाणे में मेरठ के शहर में जो अब यू.पी. में है शुरू हुआ जिसमें हरियाणें के बहुत से जवान थे। पहली लड़ाई में हमारा देश कामयाब नहीं हुआ उसके बाद अंग्रेजों ने हरियाणे को दो सजाएं दी। एक तो इसके टुकडे कर दिए और दूसरे यहां के जितने भी लीडर थे उनको बेरहमी के साथ तयतेग कर दिया गया। नतीजा यह हुआ कि यह इलाके जो अब हरियाणा है पंजाब के साथ लगा दिए गए और बाकी यू.पी. वगैरा के साथ जोड़ दिए गए। चूंकि स्पीकर साहिब लीडरशिप खत्म कर दी गई थी इसलिए तीन जनरेशन्ज तक यहां पर कोई काम नहीं हो सका। जब किसी इलाके की लीडरशिप ही खतम हो जाये ंतो उसका विकास

कैसे हो सकता है। स्पीकर साहिब जब फस्ट गरेटवार हुई तो अंग्रेजों को जरूरत पड़ी फौजी भर्ती की तो हरियाणें से जवान भर्ती किए गए। उस वक्त फिर कुछ जागृति पैदा हुई और लेट सर छोटू राम जैसे लीडरों ने होश सम्भाली। उन्होंने जब देखा कि इस तरह हरियाणें की तरक्की नहीं होगी तो उस वक्त भी आवाज उठाई गई कि हरियाणें का एक अलग सूबा बने। बराबर 40 साल तब कोशिश होती रही, कभी आवाज दब गई कभी उठ गई। आज हमें खुशी है कि हमारे वह सुपने पूर हो रहे है और हमारी हरियाणा स्टेट बन गई है। मैं जानता हूं इस स्टेट के बनने के वक्त कांग्रेस पार्टी के जो इस वक्त लीडर है उन्होंने किस कदर मुखालफित की। वह अगर महज असूली तौर पर ही मुखालिफित करते तो वह काबले बरदाश्त थी लेकिन उन्होंने हरियाणे की जनता की गैरत पर जबरदस्त ठेस पहुंचाते की कोशिश की। मैं आज अपनी बजट स्पीच पर और कुछ कहने से पहले रिकार्ड पर यह चीज लाना चाहता हूं कि हरियाणे के एक एक बच्चे की आवाज थी कि हरियाणा में संत फतेह सिंह की धमकी में आकर अगर उसके ऊपर जबरदंस्ती पंजाबी ठोंसी गई तो वह हरगिज इस चीज को बरदाश्त नहीं करेंगे। सन्त फतेह सिंह जी ने खुद यह बातें कही कि मैं हरियाणे के लोगों के साथ यह जुलम बरदाश्त नहीं कर सकता कि उनके ऊपर पंजाबी जबरदंस्ती लगाई जाए। लेकिन हरियाणे के लीडरों ने, जो आज की कांग्रेस पार्टी के लीडर हैं उन्होंने इस बात की कोशिश की कि हरियाणें में बेशक पंजाबी लागू कर दी जाए।

श्री भगवत दयाल शर्मा: क्या यह बजट पर बोल रहे हैं।

वित्तमंत्रीः मैं सबजैक्ट को छोड़कर इसलिये कह रहा हूं कि जिस लोगों को हरियाणा बनने से इतना द्वेश था उनके हाथों में हरियाणा बनने के बाद जब हरियाणे की किस्मत आई तो जिस तरीके से उन्होंने इसके साथ खिलबाड़ किया। मैं उसका जिक्र आगे चलकर करूंगा। स्पीकर साहिब मैं समझता हूं हरियाणे के लोग आज खुशी से फूले नहीं समाते कि उनके नुमायंदों के हाथों में हकूमत की बागडोर आई है। हरियाणे की फिनान्शल पोजीशन के बारे में यह कहा जाता था कि यह बाएबल स्टेट ही नहीं होगी। चुनांचे दहेजिया कमेटी के सामने यह मामला आया तो उन्होंने कहा कि हरियाणा बाएबल स्टेट हो सकती है। स्पीकर साहिब मैंने जो बजट हाउस के सामने पेश किया है उससे कई मैम्बरान को खदश हो सकात है कि यह इतना घाटे का बजट है जो हरियाणे की मुखालफत करते रहे हैं वह इसका कुछ ज्यादा ही प्रचार करते हैं। इसलिए मैं शुरू में ही यह गलतफहमी दूर करना चाहता हूं कि यह घाटा सिर्फ महज हिस्टरी के एक इतफाकिया एक्सीडेंट की वजह से है जो इस वक्त हमारे सामने है और उसका कारण स्पश्ट तौर पर हर मैम्बर के सामने होना चाहिए। कारण यह है कि भाखड़ा नंगल प्राजैक्ट जो मुशतरक्का पंजाब में बनना शुरू हुआ उसके लिए 200 करोड़ रूपए के करीब कर्जा सेंट्रल सरकार ने मुशतरक्का पंजाब को दिया। 1952 में मिला फिर 1953, 1954 और 1955 तक मिला जब तक काम होता रहा। इन सालों में ज्यादा

कर्जे की रकमें ज्वायंट पंजाब को मिली। उसकी शर्त यह थी कि हर इन्सटालमेंट उस डेट से जिसको वह मिले 15 साल के अन्दर अन्दर वापिस हो। तो जो कर्जा 1952–53 में लिया गया था वह इस साल 1967–68 में देना डियू है जो 1953–54 में लिया गया वह 1968–69 में देना होगा और जो उससे अगले साल लिया गया वह 1969–70 में देना होगा। वह जो मुशतरक्का कर्जा था वह हरियाणा के जिम्में ज्यादा कर्जा लगा या नहीं क्योंकि इस बारे में हमारा पंजाब हरियाणा का हिन्द सरकार के साथ झगड़ा है तनाजा है। मैं इस वक्त इतना कहना चाहता हूं कि ज्यादा खर्च भाखड़ा नंगल पर इन सालों में ही हुआ और उस कर्ज की अदायगी हमने इस साल आठ करोड़ करनी है और इस रकम का इस बजट में प्रोविजन किया गया है। अगले साल 10 करोड रूपया देना है और उससे अगले साल 11 करोड रूपया देना हे। यह जो आठ करोड रूप्ए की रकम हम दे रहें है इस बड़ी रकम का हमारे इस बजट पर एकदम असर पड़ा है अकेला यही कर्ज वाला आईटम आठ करोड़ रूपया खा गया है। मैं हाउस के नोटिस में यह बात खास तौर पर लाना चाहता हूं कि अगले तीन साल हरियाणा के लिए निहायत मुश्किल के समझे जाएंगे। बाकी जो हरियाणा की बजट पुजीशन है वह ठीक है मगर हम पंजाब का मुकाबला नहीं कर सकते हैं लेकिन फिर भी मैं समझता हूं कि हरियाणा के बड़े पोटेशल हैं और अगर हम इन तीन साल की मुश्किलात पर कामू पा लें तो कोई वजह नहीं कि हरियाणा बहुत जल्दी ही हिन्दुस्तान की दूसरी स्टेटस के मुकाबलें में न खड़ा हो जाए बल्कि मुझे

विश्वास है कि जिस तरह के मेहनती और नेक किसान हमारे है ओर जिस तरीके से मगरबो पंजाब से आकर बसने वाले लोगों ने मेहनत करके खैतों में दुकानों में और कारखानों में प्रोडक्शन करके हरियाणा को खुशहाल बनाने की कोशिश की है, अगर उसी तरह यह कोशिशें जारी रही जो कि जारी है तो उन कोशिशों से हरियाणा अगले चन्द सालों में हिन्दुस्तान के टाप सूबों में आ जाएगा। (चीयर्ज) स्पीकर साहिब, अब मै। बजट की तरफ आता हूं। मैं नहीं जानता कि यह कांग्रेसी भाई और बहन हरियाणा की सही बजट की तस्वीर से वाकिफ भी है या उससे इतफाक करते हैं या नहीं। मेरा ख्याल था कि ज बवह बजट पर तकरीर करेंगे तो उनका खयाल इन चीजों की तरफ होगा। हरियाणा की बुनियादी मुश्किलात का हल करने के लिए तजावीज देंगे और मदद देंगे लेकिन अफसोस है कि उनका इन मुश्किलात को तरफ कोई ध्यान नहीं गया और आप जान सकते है कि जब उन्होंने ध्या नही नहीं दिया तो वह हल क्या बताते। मैं अपनी इस स्पीच को चार हिस्सों में तकसीम करता हूं। एक तो वह कि बजट पर जनरल क्रिटीसिजम हुआ और उसका मैं जनरल तरीके से जवाब देना चाहता हूं। दूसरे सपैसफिक तौर पर नुकताचीनी की गई उसका मैं सपैसिफिक तौर पर जवाब दूंगा, तीसरे हरियाणा को फिनांशल पुजीशन की तरफ तफसील से तवजुह दिलाऊंगा और चौथे जो टैक्सेशन प्रोपोजल्ज है उसके बारे में विचार रखूंगा।

जहां तक जनरल क्रिटिसिजम का ताल्लुक है मुझे उम्मीद थी कि हमारे कांग्रेसी दोस्तो और उनमें खास तौर पर जो साबिक वजीर हैं.....(इंट्रप्शन)

श्री बंसी लाल: मालूम होता है कि उन्होंने कांग्रेसी मैम्बरान की तकरीरे सुनी नहीं है सोए पड़े होंगे। चौधरी रिजक राम जी ने और मैंने और दूसरे भी कई साथियों ने तजवीजें दी हैं। क्या फिर से बता दें?

वित्तमंत्री: स्पीकर साहिब अगर यह जरा शान्ति से सुने तो सब कुछ बताऊंगा जितने प्वांयट्स उन्होंने रेज किए थे वह मैंने अपने हाथ से लिख रखे हैं सोया नहीं था जैसा वह कहते हैं। अगर माननीय मैम्बर जरा शान्ति से हिम्मत से सुनेगे और और करेंगे तो शायद जिस हरियाणा के दर्द को लेकर ..... (शोर) .... पालियामेटरी कमेटी में जा हरियाणा का उल्आ दर्द ब्यान किया .....

Sh. Bansi Lal: On a point of Order, Mr. Speaker. Is the hon. Minister authorized to mention about the proceedings of the Parliamentary Committee on Punjabi Sua, which are confidential?

श्री अध्यक्ष: आप इस तरह इन्टरप्ट न करें अपनी बारी पर बोल लेना।

वित्तमंत्री: अगर यह प्रोवोक करते हैं तो मैं कहूंगा कि हय मैबर साहिब उन दोस्तों में से हैं जिन्होने पालियामेंटरी कमेटी में हरियाणा बनने की मुखलिफत की थी। (शेम शेम)

श्री बंसी लाल: मैं इसका सुथरा जवाब दे सकता हूं। (शोर)

वित्तमंत्री: जहां तक जनरल क्रिटिसिजम हुआ है उस बारे में कुछ दोस्तों को तकरीरों का हवाला देना चाहता हूं। मिसाल के तौर पर श्री प्रभु सिंह ने कहा कि देखिए साहिब मुजारों का गला काट दिया गया हरिजनों से मुजारों से ब्लैक मनी कमाया गया 40 लाख की जमींन चार करोड़ में बचा दी। फिर बंसी लाल जी ने कहा कि देखो कितनी शर्म की बात है कि तीन हजार मुरब्बा मील हरियाणा में पीने का पानी नहीं मिलता हे और एक साहिब शायद वह दया कृष्ण जी थे। वह कहने लगे कि पुलिस का इंतजाम कितना निकम्मा है। अंग्रेज अच्दा ढांचा छोड़कर गए थे वह इतना खराब किया गया है और अब भी उस ढांचा में कुछ कसर है और काबिले तारीफ है। मैं यह बातें सुनकर हैरान हो रहा था कि आखि रवह सज्जन किसको यह सरटीफिकेट्स दे रहे थे यह बातें कह कह कर.....(शोर) जितनी बातें इन्होंने की वह एक तरीके से इनकी 20 साल की काली करतूतों का कच्चा चिट्ठा था जो खुद अपने मुहं से ब्यान कर रहे थे.....(शोर)..... फिर बहन लेखवती जी ने कहा कि एक गांव पता नहीं खुड्डा का नाम लिया कि देखो वहां पिछले 80 साल से एक प्राईमरी स्कूल

चल रहा है उसको अच्छी इमारत है लेकिन मिडल स्कूल नहीं बनाया। यह बात कहते बहन जी ने यह नही सोचा कि हमने तो अभी दो महीने से चार्ज सम्भाला है लेकिन इससे पहले जो 20 साल तक वह और उनके कांग्रेसी भाई हकूमत करते रहे वह क्या करते रहे और अगर वह मिडल नहीं किया गया तो उसकी शर्म किसको आनी चाहिए हमें या उनको ? ..... शोर ..... फिर श्री केसरा राम जी उठे और कहने लगे कि बैटरमेंट लेवी के शायद 19 किश्तें दे चुके हें और हम हिसाब लेना चाहते हैं लेकिन कोई नहीं देता है सच मानें ज बवह इस तरह की मिसाले देते थे तो मुझे शर्म आती थी कि कांग्रेस सरकार के 20 साला मिसरूल की मिसालें तो वह उठ उठ कर दे रहे थे लेकिन उससे अब भी चिपके बैठे है और उन्हें शर्म नहीं आती ..... शोर .....

श्री रण सिंह: स्पीकर साहिब, यह पूछ रहे हैं कि शर्म किसको आनी चाहिए तो मैं अर्ज करता हूं कि शर्म इनको ही आनी चाहिए और चौधरी चांद राम को अपनी चाहिए जिन्होने धोका दिया है ..... शोर .....

वित्तमंत्रीः स्पीकर साहिब मेरे इनल ायक दोस्तों ने बारी बारी खड़े होकर चार्ज किया कि वह बड़ी अनपापूलर सरकार है और उसक टैस्ट इन्होंने यह बतलाया कि 10/15 आदमी कांग्रेस से संयुक्त दल में चले गए। इनकी यह बात सुनकर मुझे महाभारत की एक कहानी याद आ गई है। शिशुपाल कृष्ण जी महाराज को बहुत गालियां देते थे और वह बरदाशत करते रहे। सब ने कहा

कि महाराज आपको शिशुपाल बहुत गालियां दे रहा है और बरदास्त कर रहे हैं ऐसा क्यों अब तो हद हो गई है उसे बन्द करना चाहिए। कृष्ण जी ने काह कि कोई बात नहीं इसे सौ गालियां देने का वर है और अभी सौ पूरी नहीं हुई हैं सौ गालियां पूरी होते ही उसका सफाया हो जाएगा .....(शोर) ..... तो हम भी साहिब बंसी लाल जी और ओम प्रकाश जी मेरे दोस्त यह बरदाश्त करते रहे कि यह कांग्रेस की जमायत अब भी ठीक होगी और अब भी ठीक होगी।

श्री ओमप्रकाश शर्मा: यह बिल्कुल गलत है।

श्री अध्यक्ष: आप बैठे जाइए।

(ओम प्रकाश शर्मा: शोर में कुछ बोलते हुए खड़े रहे।)

श्री अध्यक्ष: आप नहीं बैठेंगे? (ओम प्रकाश शर्मा नहीं बैंठे) आल राडट यु लीव दी हाऊस।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: फिर कितनी देर में वापिस आऊं। (हंसी)

श्री अध्यक्ष: जब मर्जी।

वित्तमंत्री: स्पीकर साहिब, मैं इस विषय पर और ज्यादा नहीं कहना चाहूगा केवल एक दो फिकरे कह कर खतम कर दूंगा। कांग्रेस को छोड़ना या न छोड़ना कोई धर्म की बात नहीं है। आजादी से पहले तो धर्म की बात थी। अगर कोढ कहे कि किसी

आदमी को परखने के लिए यह कसौटी है तो यह नहीं मानता। किसी जमायत में रहने के लिए तो मेरे कांग्रेस भाईयों की एक ही कसौटी है और वह यह कि आया उस जमाया में रह कह कोर्ठ व्यक्ति अपने देश और प्रदेश की सवा कर सकात है या नहीं। अगर किसी कृरप्ट आदमी को ही आगे आना है ओर सब बातें साबित होने के बाद भी यदि ऐसा व्यक्ति ही कांग्रेस की ही पार्टी का लीडर हो सकात है (कांग्रेस की तरफ से शोर) तो मैं समझता हूं कि जितने जल्दी उस जमायत को छोड़ा जाए उतना ही हरियाणा के लिए और देश के लिए अच्छा है। स्पीकर साहिब इन चीजों को देखकर अगर मेरे दोस्त कहें कि अनपापूलर गवर्नमेंट का अनपापूलर बजट है तो यह ठीक नहीं। पापुलेरिटी का सार्टिफिकेट तो यहां की जनता ने पिछले इलैक्शन में दिया है और फिर बहादुरगढ़ का हाल ही का चुनाव इसका सबसे ज्यादा सबूत है (ट्रेजरी बैंचिज की तरफ से तालियां)। स्पीकर साहिब ये अपनी ज्यादतियों को भूलते हुए हम पर इलजाम लगा रहे हैं। मैं तो कहता हूं कि इसके लिए एक फोरम खुला है। इलैक्शन पैटिशन कीजिए, इलजाम वहां लगाइए और साबित कीजिए वरना इस तरीके से झेंप उतरती नहीं और इस तरीके से काम नहीं चलता। खैर, अब मैं स्पीकर साहिब, इनकी स्पैसेफिक बातें जो हैं उनकी तरफ आता हूं। चौधरी रिजक राम जी ने शुरू करते हुए कहा कि बजट में बहुत इम्बेलेसीज हैं। इम्बेलेन्स क्या बताते हैं वे, कि देखिए साहिब एक तरफ तो मालगुजारी माफ की और दूसरी तरफ लैंड रेवेन्यू ड्योढ़ा कर दिया। मैं उनकी बात नहीं

समझ सका। अरे भाई इस ड्यीढे में तो वे पांच एकड़ वाले तो नहीं आयेंगे। यह तो पांच एकड़ से ऊपर वालों को है। और फिर यह जो टैक्स है यह कुरूक्षेत्र युनविर्सिटी के सुधार के लिए एक साल के लिए हैं। इसी तरह से स्कूल जो अपग्रेड किए गए उनकी आलोचना की गई। मै। तो समझता था कि इस बात की प्रशंसा होगी और जो जायज नुक्ताचीन होगी उसको हम सुनेंगे और जिस चीज में दुरूस्ती करने की गुंजायश होगी उसे करेंगे। जैसे, मान लो किसी जगह स्कूल अपग्रेड हो गया परन्तु उसकी जगह दूसरे स्थान पर वह ज्यादा ुायदेमें हो सकात है तो हम उसे बदलने की सोच सकते थे। लेकिन यहां पर तो इस तरह की कोई बात नहीं आई बल्कि यह कहा गया कि यह फिजूलर्खी है और जो काम पांच साल में होना था वह संयुक्त दल की सरकार ने एक साल में क्यों कर दिया। मैं तो स्पीकर साहिब, हैरान हूं कि न तो इन्होने फर्स्ट फाईव इयर प्लान, सेकिड फाइव इयर प्लान और थर्ड फाइव इयर प्लान की कोई रिपोर्ट पढ़ी और न ही कम्युनिटी डिवैल्पमेंट वालों ने जा इतने पैम्फलैट्स और जरनल आदि निकाले हैं वे इन्होने पढ़े। इनमें लिखा है कि एग्रीकल्चरन या इनडस्ट्री में चाहे कितनी इनवैस्टमेंट हो जाए लेकिन सबसे बड़ी इनवैसटमेंट इन मैन होती है। तो यह तालीम जो है यह इनवैस्टमेंट इन मैन है। क्या मेरे लायक दोस्त इस बात से इनकार करेंगे कि एक पंजाबी, चाहे वह खेती करता है, चाहे इनडस्ट्रियलियस्ट है, चाहे बिजनैस करता हे या चाहें सरकारी कर्मचारी है हरियाणा के एक लोकल बासिन्दे से ज्यादा काम करता है। इसका क्या कारण हे। इसका कारण यही है

कि वे हमारे से ज्यादा तालीम याफता हैं। एक ही वर्ष में सयुक्त दल की सरकार इतनी हिम्मत करे कि जो स्कूल चार या पांच वर्ष में अपग्रेड होने थे वे दो महीने के अन्दर अन्दर कर दिए तो क्या यह भी आपकी नुक्ताचीनी का कारण हो सकता है?

श्री बंसी लाल: आन ए प्वायंट आफ आर्डर सर। नुक्ताचीनी तो यह है कि किसी जगह पर 11 स्कूल अपग्रेड हुए और किसी जगह पर एक भी नहीं।

श्री अध्यक्ष: यह कोई प्वायंट आर्डर हुआ।

वित्तमंत्री: तो स्पीकर साहिब यह क्रिटिसिजम कि जो पैसा हमने स्कूलों को अपग्रेड करने में लगाया है वह टयूबवैल्ज के लिए देना चाहिए था बिल्कुल बेबुनियाद है रही बात यह कि खुड्डे में स्कूल अपग्रेड होना चाहिए था इसके बारे में अर्ज यूं है कि खुड्डे की तरह बहुत से गांव अभी और भी बाकी हैं जहां स्कूल होने चाहिएं।

श्रीमती लेखवती जैन: मैं चैलेंज करती हूं। (शोर)

श्री अध्यक्ष: आप बैठ जाइयें बहिन जी। (विघ्न)

वित्तमंत्री: तो स्पीकर साहिब, मैं कह रहा था कि कांग्रेसी भाईयों का यह कहना कि यह फजुलखर्ची है ठीक नहीं।

श्री ओम प्रकाश शर्मा: आन ए प्वाइंट आफ आर्डर सर। आपोजिशन की तरफ से यह बात नहीं आई कि यह फजुलखर्ची है।

श्री अध्यक्ष: यह क्या कोई प्वांइट आफ आर्डर है? देखिए ओम प्रकाश जी, मैं प्वायंट आफ आर्डर को मना नहीं करता। आप एक एक मिनट के बाद उठाइए। लेकिन प्वायंट आफ आर्डर तो कोई उठाता ही नहीं। लोगों को कहना होता है और प्वायंट आफ आर्डर रेज करने लग जाते हैं।

श्री बंसी लाल: स्पीकर साहिब, वित्तमंत्री साहिब से कहिए कि वे कोई कन्ट्रोवरशियल बात न कहें ताकि कोई झगड़ा ही न हो।

वित्तमंत्री: मैं तो स्पीकर साहिब इतना ही बताना चाहता था कि हमने जितने स्कूल अपग्रेड किये हैं हम उससे भी ज्यादा अपग्रेड करेंगे (तालियां)। आपकी इजाजत से मैं यह थोड़ी सी फिगर्ज एजूकेशन के मामले में हाऊस के सामने रखना चाहता हूं। चौथी पंचवर्षीय योजना में जनरल एजूकेशन के लिये केवल 11 करोड़ रूपया रखा गया है जो कि टोटल प्लान का 6.21 परसैन्ट है जबकि इसके मुकाबले में थर्ड फाइव इयर प्लान में एजूकेशन पर 7.7 परसैंट खर्च हुआ है। हमारे तो तालीम पर खर्च थर्ड फाइव इयर प्लान से भी कम हैं फिर भी यदि मेरे दोसत कहें कि फजूलखर्ची है तो यह बिल्कुल गलत हैं अब रही अपग्रेडिंग की

बात। श्री राम किशन आजाद, जो यहां मैम्बर हैं, मैंने उनके जिाल का स्कूल अपग्रेड कराया। मैंने खुद

11.00 A.M.

मिनिस्टर कसन्र्ड को कहा कि जलवाना का स्कूल अपग्रेड करें। श्रीमती लेखवती जैन जी ने भी कहा। स्पीकर साहिब, अगर मेरे भाई और बहनें बैठे बैठे ही बातें करें और मिनिस्टर साहिबान के नोटिस में कोई बात न लाये ंतो उन्हें कैसे पता लगेगा कि कहां कौन सा स्कूल अपग्रेड करना है। (इंट्रप्शन)।

मुख्य संसदीय सचिवः स्पीकर साहिब, मिनिस्टर साहिब यह बात बार बार कहते है कि ..... (इंट्रप्शन)

श्री अध्यक्षः आप बैठ जाइए।

वित्तमंत्रीः स्पीकर साहिब, स्कूलों के अपग्रेडिंग के बाद एक और क्रिटिसीजम शुरू हुआ, वह है गवर्नमेंट इम्पलाईज को महंगाई भत्ता देने के बारे में। यह सब को मालूम है कि हरियाणा प्रान्त की माली हालत कितनी टाईट है, जिसका जिक्र मैंने अभी अभी किया है। इतनी टाईट पोजीशन के बावजूद, जब कि सात आठ करोड़ रूपये का बजट मजीद घाटे का है, हमारी सरकार ने हिम्मत करके, महंगाई से दबे हुए सरकारी कर्मचारियों को सैंट्रल रेट पर भत्ता दिया। इसके बाद स्पीकर साहिब, कई लोगों के पेट में दर्द होने लगा कि सरकार कर्मचारियों के साथ बेइन्साफी की जा रही है। इसके बाद सरकारी कर्मचारियों की तरफ से आफर

आई, जिसको मैं पढ़कर सुनाता हूं। हमारे सरकारी कर्मचारी हरियाणा प्रान्त के भक्त हैं और वे सारी मुश्कलात को जानते हैं, जिसका जिक्र इन्होंने इस आफर में किया है, मैं इसको एप्रिशिएट करता हूं –

" A deputation of Haryana Subordinate Services Federatin had met the Finance Minister, Hrayana, on 8th May, 1967 for negotiating the demands of the Haryana Government employees, in particular their demands for the grant of D.A. at central Governemnt rates. The deputation appreciated the financial difficulties of the State Government and agreed that in case full quantum of the D.A. at central rates cannot be granted by the Government, they may kindly consider the desirability of granting D.A. at Central rates in the following manner :-

(i) the meployees drawing basic pay below Rs. 100 per mensem may invariably be allowed D.A. at Central rates in cash.

(ii) The government may also allow D.A. at Central rates, in cash, to the employees drawing basic pay between Rs. 101 to Rs. 300, if possible, so as to lessen their financial liabilities owing to the rising prices. If not, para III bwlow may be followed.

(iii) The employees drawing salary above Rs. 300 per mensem may be given D.A. at Central rates, 50 per cent in cash and the remaining to be deposited in the G.P. Fund. Those who do not contribute towards G.P. Fund may either open G.P. Fund Account or deposit the remaining amount in

C.T.D., Small Savings Certificates, etc., as the Government may deem fit.

The above suggestions are still agreeable to the members of the Federation."

इससे पता चलता है कि हरियाणा के कर्मचारी हरियाणा के भक्त हैं। उन्होंने खुद कहा कि हम हरियाणा की माली मुश्कलाता को जानते हैं। इसके बावजूद के कहते हैं कि सौ रूपये से कम वेतन पाने वालों को पूरा भत्ता दे दिया जाए और तीन सौ रूपये वेतन पाने वाले को आधा दे दें। इसकी चिट्ठी चीफ मिनिस्टर साहिब को भी गई होगी। स्पीकर साहिब मै। हरियाणा प्रान्त के कर्मचारियों की सराहना करता हूं और उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूं कि उन्होंने हरियाणा की माली हालत की मुश्कलात को पहचानते हुए यह आफर पेश की कि सौ रूपये तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को पूरा भत्ता दे दिया जाए और इससे ऊपर वालों का आधा सी.टी.डी. में जमा करवाने के लिये काट लिया जाए .....

चौ. रिजक राम: स्पीकर साहिब, मैं मिनिस्टर साहिब से इस बात को क्लैरिफिकेशन चाहता हूं कि जो रकम सी.टी.डी. में जमा होगी वह आपके फण्ड में कैसे आयेगी? इसका ताल्लुक तो सैंटर से है।

वित्तमंत्री: यह आपने एक नाया प्वायंट उठा दिया। यह कोई पत्थर पर लकीर नहीं कि यह रकम सी.टी.डी. में ही जमा की

जाए। आधी रकम जमा करने के लिये एक आर्डर जारी कर दिया जायेगा कि आधी रकम प्रोविडेंट फंड में जाम कर दी जाए।

स्पीकर साहिब, मुझे बड़े दु:ख के साथ कहना पड़ता है कि एक तरफ तो हरियाणा के कर्मचारी हरियाणा के प्रति भक्ति का इजहार करते हैं और दूसरी तरफ भूख हड़तालें करते फिरते हैं। लेकिन इस आन्दोलन में सब कर्मचारी शामिल नहीं हैं, जो ब्लैकशीप हैं, वही इसमें भा ले रहे हैं। वैसे तो ब्लैकशीप हर जगह होते हैं। रोज अखबारों में इस बात का प्रोपोगंडा हो रहा है। सिर्फ ब्लैकशीप ही इस किस्त की बातें करते हैं। हरियाणा में 96 हतार सरकारी कर्मचारी हैं, उनमें से पांच सात फीसदी कर्मचारी हैं जो अखबारों में प्रोपागंडा करते हैं। इस सिलसिले में स्पीकर साहिब, एक बात कहना चाहता हूं। हरियाणाप्रान्त के 96 हजार सर्विसिज में से कुछ भाई ऐसे हैं जो बाहर से आकर यहां आबाद हो गये हैं और जो आबाद नहीं हुए हैं वही इस किस्म की बातें करते हैं।

अब मैं डिवीजन आफ् ऐसेट्स के बारे में जिक्र करना चाहता हूं। कुछ भाईयों ने यहां कहा कि पजाबी भाईयों ने हरियाणा को नुक्सान पहुंचाया। इसके बारे में मुझे यह बताते हुए खुशी होती है कि जितनी तनदेही और खुशअसलूबी से, हरियाणा में आये हुए उन अफसरों ने, जिनका पंजाब डोमिसाइल है, जितनी मजबूती से, हरियाणा प्रन्त के हितों की रक्षा की, उसकी तारीफ करने के लिये मेरे मुंह में शब्द नहीं हैं। (तालियां)

स्पीकर साहिब, जब रीआर्गेनाईजेशन एक्ट बना, उसमें एक प्रोवीजन है कि जो प्रापर्टी पंजाब की पंजाब से बाहर है उसकी तकसीम के बारे पंजाब को मिलेगी। मुझे स्पीकर साहब, जिस चीज का दु:ख है, वह मैं आपके सामने लाना चाहता हूं। मैं दहेजिया कमेटी की बात हाऊस के सामने बतलाना चाहता हूं। इस कमेटी ने कुद अजम्पशन्स किए और उसके खिलाफ किसी ने प्राटैस्ट नहीं किया।

श्रीमती ओम प्रभा जैन: प्रोटैस्ट किया गया।

वित्तमंत्री: मैं देखना चाहूंगा अगर कोई प्रोटैस्ट किया गया तो। जनाब इन्होंने बगैर किसी प्रोटैस्ट के चंडीगढ़ का मामला प्राईम मिनिस्टर के हाथों में दे दिया।

इसके बाद यहां पर हमारे आई.एस.एस. ओर आई.सी. एस. अफसरों ऊपर आक्षेप किया गया जो ठीक नहीं। क्योंकि अफसर चाहे पंजाब का रहने वाला हो चाहे हरियाणा का रहने वाला हो, इन्होंने बहुत बड़ी सच्चाई और ईमानदारी का सबूत दिया है।

श्री बंसी लाल: क्या वित्तमंत्री महोदय को याद है कि इन्होंने पालियामेंटरी कमेटी में पंजाबी अफसरों के बारे में बहुत बहुत बातें डेरोग्टरी कहीं थी और यहां तक कि जो भाई वैस्ट पाकिस्तान से आकर हरियाणा में आबाद हुए है उनके खिलाफ भी

दिल खोल कर बोले थे। लेकिन चलो अब यह कहते हैं तो ठीक है, जब अक्ल आ जाए तभी ठीक है। (विघ्न)

वित्तमंत्री: चौ. रिजक राम जी ने अपने विचार रखते हुए यहां हाउस में काह था कि यह मिनिस्टर तो नवाबों की तरह रहते हैं इसलिये जनता को क्या उपदेश दे सकते है? लेकिन मैं उन्हें यह बतलाना चाहता हूं कि मिनिस्ट्री में आने से पहले मैं इससे बहुत अच्छी तरह रहता था जितना अब रह रहा हूं। और वजीर बनने के बाद रहने की परवाह न करते हुए बहुत काम कर रहा हूं।

मैं बीच में इन बातो ंको लाया। लेकिन मैं स्पीकर साहिब यह कह रहा था कि दहेजिया कमेटी की रिपोर्ट की वजह से या पंजाब रीआर्गेनाइजेशन ऐक्ट में जो प्रावीजन किया गया उसकी वजह से हरियाणा के साथ बहुत ज्यादती हुई। एक पालिसी यह बनाई गई कि लोकेशन की बिना पर तकसीम हुई। यानी नहर बारी दुआब जो पंजाब मे ंआती है वह पंजाब में दी गई। इसकी वजह से हुआ यह कि इन चीजों की वैल्यू कुछ नहीं रही। ओर इस प्राकर जो हमारा हिस्सा बन सकात था वह कुछ नहीं रहा। इसी तरह पंजाब में डिवैल्पमेंट हुआ और सड़कों का जाल बिछा लेकिन चूंकि वह लोकेशन की बिना पर तकसीम हुई इसलिये हमारे हिस्से में उनका हिस्सा भीकुछ नहीं मिला क्योंकि उनकी कोई वैल्यू नहीं थी।

अब हरियाणे के लिये स्पैशल ऐसिस्टेंस का केस जो बनता है उसके विषय में कहना चाहता हूं। हरियाणा की तकसीम अगर यकम नवम्बर सन् 1966 से पहले होती तो हरियाणा को वे सक ऐडवाटेजिज मिलते जो सैंट्रल गवर्नमेंट ने फाइनेंशल कमीशन के द्वारा दूसरी स्टेट्स को दिए। और खासतौर से सैंट्रल ऐक्साइज डयूटी की तकसीम में किसी स्टेट को 20 करोड़ किसी को 30 करोड़ रूपया सालाना मिला है। इसी तरह हमारे हरियाणा का केस हैं और यह लाजिमी था कि हमारे फाइनैशल आस्पैक्ट को देखते हुए उस हिसाब से 15 करोड़ रूपया मिलता। लेकिन सिर्फ एक साल तकसीम डिले होने की वजह से वह शर्तें अब हरियाणा पर लागू नहीं है। इस सम्बन्ध में हमारे चीफ मिनिस्टर ने सेंटर को चिट्ठी लिखीं हैं और डिमांड की है कि हमें भी वह फैसिलीटीज मिलनी चाहिए। आपसे मेरा निवेदन है कि आप भी कोआपरेट करें।

श्रीती ओम प्रभा जैन: जरूर देंगे सहयोग।

वित्तमंत्री: इसी तरह से भाखड़ा के क्रेडिट में हमें नुक्सान उठाना पड़ा। अगर इसकी तकसीम पहले हो जाती तो हमारे ऊपर बोझ न पड़ता। भाखड़ा का फायदा पंजाब ने लिया और कर्ज ही कर्ज हमारे ऊपर पड़ा जो हम मुश्तरक्का पंजाब में मिलकर देते रहे। मैंने पहले भी कहा था पार्लियामेंटरी कमेटी में कि पंजाब के लोग हमारे साथ सौतेली मां जैसा सलूक करते हैं। तो मैं उस कर्जे की बात कर रहा था कि अगर हरियाणा 3 साल

पहले तकसीम होता तो कर्जे की पेमेंट अदायगी के लिये न रहती। हमने गवर्नमेंट आफ इंडिया को लिखा था कि कर्जे की इतनी भारी भारी रकमें 3 साल में न लो बल्कि इसे स्पिलिट करके 15 सालों में इक्वेटिड इंस्टालमेंट में ली।

ब्यास प्रोजैक्ट के लिये कर्जा लिया है उसकी पेमेंट भी आए साल करनी पड़ती है पबकि अभी उसका फायदा कुछ नहीं हो पा रहा और सूद की किस्तें बराबर दे रहे हे। मेरी अपनी यह है कि साल के साल सूद न लेकर कर्जा को कैपिटलाइज कर दिया जाए और उगराही उस वक्त से शुरू हो जब हमें पानी और बिजली मिलने लगे। इसके इलावा, स्पीकर साहिब, यहां मैम्बरों ने रोष प्रकट किया कि देहाती आबादी को भी चीनी का कोटा पूरा मिलना चाहिए। मैं उनके साथ सहमत हूं लेकिन चीनी की बात तो एक तरफ रही सैंट्रल सरकार ने हमें इम्पोर्टिड कीट का जो हमारा कोटा बनता था वह भी पूरा नहीं दिया। आप गवर्नमेंट आफ इंडिया की हाई हैडिंडनैस का मुलाहजा फरमाइए जिसको आपकी पार्टी कंट्रोल करती है। उन्होंने अंदाजा लगाया कि हरियाणे में पिछले सालों में चीनी की खपत कम होती रही है और पंजाब में ज्यादा होती रही है इसलिये हरियाणे की कम मिलेगी क्योंकि लोग चीनी खने के आदी नहीं है। आप अंदाजा लगाये कि किस किस्म का क्रइटेरिया है उसका स्पीकर साहिब हमारा जमना के पास जो खादर का इलाका है वहां देसी खांड ज्यादा पैदा होती है। पहले जब चीनी आसानी से मिलती थी तो देसी खांड का रेट चीनी से

क्योंकि बहुत कम होता था इसलिये गरीब लोग ज्यादातर देसी खांड से ही गुजारा कर लिया करते थे। लेकिन अब स्पीकर साहिब देसी खांड तीन रूपए किलो से कम नहीं मिलती जबकि चीनी का भाव 1.50 है। इसलिये अब सब चाहते है कि हमें भी चीनी का कोटा मिलें। अब अगर उनको मिले तो वह 1.50 वाली चीनी को छोड़ कर देसी खांड क्यों खाएंगे। इसलिये क्यों न हमको भी उसी हिसाब से चीनी का कोट दिया जाए जैसे कि दूसरो स्टेटो में या पंजाब में दिया जाता है। अगर चीनी की पैदावार कम हुई है तो बेशक न दिया जाए। लेकिन अगर हमें इसलिये कम दिया जातउ है हमारे लोग खाते नही या यह नान–कांग्रेस सरकार है तो यह बातें जायज नहीं लोग इस बात को अच्छी तरह जानते है कि अगर हमें चीनी नहीं मिलरही तो इसमें सैंटर की सरकार का कसूर है न कि संयुक्त दल की सरकार का। जहां तक इम्पोर्टिड व्हीट का ताल्लुक है जनवरी और फरवरी में भारी तादाद में आई और वह सस्ते भाव पर बिकी लेकिन उसके बाद हरियाणा मैं अब क्यों नहीं इम्पार्टिड व्हीट दी जा रही। स्पीकर साहिब मैं यह चाहता हूं कि हम उनको कहें कि हम चावल तब आपको देंगे, अगर आप पहले हमें इम्पोर्टिड व्हीअ का कोटा देंगे। हम चाहते है कि वह हमें इम्पार्टिड व्हीट का कोटा महीने के महीने देते रहें ताकि हम अनाज को कीमतों को कंट्रोल कर सकें। इन बातो में आप हमें सहयोग दें जितना भी आप दे सकते हैं।

EXTENSION OF TIME OF THE SITTING

Mr. Speaker: Should we extent the sitting by half an hour?

Voice: Yes.

Mr. Speaker: The sitting is extended by half an hour today.

GENERAL DISCUSSION ON BUDGET (RESUMPTION)

वित्तमंत्री: कुछ यूजफुल सजैशन्ज कांग्रेस के मैम्बरों से और हमारे दल के मैम्बरों से भी आए हैं। मिसाल के तौर पर चौधरी रिजक राम जी ने कहा कि सरकारी स्कूलों में फ्री एजूकेशन है इसको हटाकर फोस लगा दी जाए जैसे कि प्राईवेट स्कूल्ज में ली जाती है। उन्होंने मिसाल देकर कहा कि करनाल, पानीपत और रोहतक वगैरा में प्राईवेट स्कूलों में फीस लेते हैं और सरकारी स्कूलों में नहीं लेते। उनकी सजैशन में काफी वनज है लेकिन उनको पता होना चाहिए कि फीस न लेने का तरीका तो उनकी सरकार ने ही जारी किया था। उनकी सजैशन काफी मुनासिब है। हरिजनों को कनसैशन देने के इलावा और 20/25 प्रतिशत गरीब मां बा पके बच्चों को फिस का कनसैशन देने के इलावा बाकी सबसे फीस लेने पर गवर्नमेंट विचार करेगी।

इसके इलावा स्पीकर साहिब कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के टैक्स के बारे में बड़ी नुक्ताचीनी की गई। एक साथी ने तो यह कहा कि कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी के लिये टैक्स लगाने की बजाए पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ एफीलियेशन है उसको हटा लो तो

खर्चा पूरा हो जाएगा। यह उनकी सजैशन बिलकुल गलत हैं हम पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ उसी तरह एफीलिशिएशन रखेंगे। लेकिन मैं यह कहना चाहता हूं कि जहां तक पंजाब यूनिवर्सिटभ की सैनेट का, इंतजाम का और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का ताल्लुक है हरियाणे का उसमें इस समय नफी के बराबर हिस्सा है और वह बढ़ नहीं सकता जब तक यह मौजूदा सैनेट वगैरा तबदील न हो। उन्होंने दफा 72 का हवाला दिया है कि हम हिन्द सरकार को लिखें। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जो कुद भी हो सकेगा हम वह तमाम जरूरी कदम उठाएंगे और जो हरियाणे का हिस्सा होना चाहिए उसे मांगने की पूरी कोशिश करेंगे।

इसके इलावा भिवानी तहसील के बारे में श्री प्रभाकर और बंसी लाल जी ने कुछ बातें कहीं। मैं मानता हूं वाकई भिवानी, महेन्द्रगढ़ और लोहारू के ऐसे इलाके हैं जिन को देखकर ताज्जुब होता है कि 20 साल तब कांग्रेस सरकार करती क्या रही तीन हतार मुरब्बा मील में पीने का पानी भी नहीं है। किस तरह बेचारे लोग परेशान हैं। स्पीकर साहिब हमारी सरकार ने इस साल के लिये 66 लाख रूपए का प्रोविजन किया है और अगर फाइनैन्शिल पोजीशन टाईट न होती तो हमारा दिल तड़पता था कि आजादी के 20 साल बाद भी कांग्रेस सरकार की मेहरबानी से 3 हजार मुरब्बा मील में पानी का पानी नहीं दे सकी हम उनको ज्यादा से ज्यादा सहूलत दें। बहरहाल मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम कुछ एरिया में जल्दी ही पाने का पानी का जरूर

इन्तजाम करेंगे। एक और बात का मे। पासिंग रैफरैंस दूंगा क्योकि बजट के आंकड़े बिलकुल कलियर हैं। कुछ दोस्तो ने कहा कि सारे देश में अनाज का संकट है और कोई भी सरकार जिसके दिल में हमदर्दी है वह लाजमी तौर पर सबसे ज्यादा तवज्जो अनाज पैदा करने के लिये देगी। हमारा तो स्पीकर साहिब एक एक लफ्ज पुकार पुकार कर कह रहा है कि हमने पैदावार बढाने के लिये खास तवज्जों दी है। 28 करोड़ रूपये की स्कीमें हैं। 32/33 करोड़ रूपए में से 75 रूपया एग्रीकल्चर के बढावे के लिये माइनर और मेजर इरीगेशन की स्कीमों के लिये हैं। हैरानी की बात है कि यह सारे आंकडे बजट में मौजूद है लेकिन इसके बावजूद कहते है कि ऐग्रीकल्चार की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया है। मैं कहता हूं कि एंग्रीकल्चर का तो एक तरह का क्रेश प्रोग्राम है जो इस बजट में रखा है इसके जैसे जैसे बजट की पुजीशन ठीक होती जाएगी और भी ध्यान देंगे। इसके अलावा यह जो आबयाना बढ़ा था वह तो आपको पता है कि वापिस ले किया है।

चौ. रिजक राम: वह तो चीफ मिनिस्टर साहिब ने वापिस ले लिया मालगुजारी आप वापिस ले लें।

वित्तमंत्री: यह हमें कुरूक्षेत्र यूनिवर्सिटी को फिनांस के लिये बढ़ाना पड़ा। यह जगह सारे हिन्दुस्तान में मुत्तबरक है और ऐसे मुत्तबरक स्थान के नाम पर जो यूनिवर्सिटी बने तो उसे आगे बढ़ाना हम सबका फर्ज है ....

चौ. रिजक राम: क्या इसकी किसानों पर ही जिम्मेदारी पड़ती है?

वित्तमंत्री: यह सबकी ही जिम्मेदारी है आज इस सरकार की जिम्मेदारी है दो महीने आपकी जिम्मेदारी थी। यह आरजी टैक्स है एक साल के लिये और पचास फीसदी प्रापर्टी टैक्स में बढोत्री की है। पांच एकड़ वालों तक इसका कोई असर नहीं पड़ेगा और पांच एकड़ के ऊपर वालों पर ही एक साल के लिये डेढ गुना किया हे। इसके बाद शो टैक्स पर नुक्ताचीनी की गई है कि सिनेमा हाउस की सीटिंग कैपिस्टी को मद्देनजर रखते हुए ही यह टैक्स दुगना कर दिया गया है लेकिन होना यह चाहिये था कि जो अकुपाइड सीट्स हों उनके बेसिज पर ही यह टैक्स लगनाचाहिए। मैं मानता हूं कि इस दलील में कुछ वनज हो सकात है लेकिन मैं इस बारे में इस वक्त कुमिट नहीं करता कि सरकार क्या करेगी मगर मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि हम इस चीज को देखेंगे गौर करेंगे कि कपैस्टी पर लगे या आकोपाइड सीट्स पर लगना चाहिये .....

चौ. रिजक राम: वह तो मान ही जायेंगे (हंसी)।

वित्तमंत्री: मोअर स्पिरिट पर जो टैक्स कम करने का ऐलान किया है उस बारे में देहाती शहरी की बात पैदा करने के लिये नुक्ताचीनी कर दी है हालांकि साफ तौर पर लिखा है कि पहले जो हमें आमदनी होती थी उसमें इस टैक्स के बढ़ाने के

बाद कमी हो गई है क्योंकि टैक्स ज्यादा हो की वजह से जो आदमी देहात से चंडीगढ़ आता है यह अपनी कार की टैंकी देहली से ही फुल करा कर लाता है और करनाल अम्बाला वगैरा कहीं भी तेल नहीं लेता ओर इस वजह से तेल से जो बिक्री टैक्स आता है उसमें कमी हो गई है हरियाणा मं अगर तेल महिंगा मिलैं और दूसरी जगह देहली वगैरा में सस्ता मिले तो कोई क्यों हरियाणा में तेल खरीदेगा हरकि कोशिश करता है कि वह पैसे बचाए तो इसका असर हमारे रैवेन्यू पर पड़ा है और इस टैक्स से हमारी आमदनी कम हो गई है। इस चीज को देखते हुए हम यह रेट दहली के मुकाबले पर करना चाहते हें ताकि लोग देहली जाकर ही तेल न खरीदें। अम्बाला, रोहतक करनाल में भी खरीद करें और हमारी आमदनी में इससे बढौतरी हो। फिर जो मिनरल टैक्स दुगना किया गया है उसके बारे में हीरानन्द जी ने कहा कि किसान ही मकान बनाने के लिये कंकर खोदते हैं उनको ऐग्जैम्पट किया जाए। मैं इस चीज को इस वक्त स्टडी नहीं कर सका कि रूल्ज में ऐसा करने की गुंजाइश है या नहीं अगर कानून में गुंजाइश होगी तो एकजैंप्शन दे देंगे लेकिन अगर मौजूदा ऐक्ट में गुंजाइश नहीं होगी तो उसे तरमीम भी कर देंगे और किसानों को रियायत देंगें। (चीयर्ज) भट्टों पर जो फी ली है वह जरूरी थी क्योंकि जो खर्च भट्टों की निगरानी के लिये इन्सपैक्टर पर होता है वह तो निकल सके। चावल पर जो परचेज टैक्स लगा है उसके बारे में अर्ज है कि यह टैक्स किसानों पर नहीं लगता है। यह चाल गवर्नमेंट आफ इंडिया खरीदती है और वही कीममत

मुकर्रर करती है। यह परचेज टैक्स गवर्नमेंट आफ इंडिया पर ही लगेगा किसान पर नहीं।

चौ. रिजक राम: चाही रेट का भी बता दें।

वित्तमंत्री: चाहि रेट के बारे में जो मार्च में ऐलान किया था हम उसी पर कायम हैं। अब मैं खतम करने से पहले एक अर्ज और करना चाहता हूं। हमारे हरियाणा में पांच किसम की आबादी है। पहली है एग्रीकल्चरल लेबर जिसमें हरिजन भाई आ जाते हैं और दूसरे लैंडलैस लोग आ जाते हैं। उनके बारे में इस बजट में कितना कुछ किया है मुझे खुशी है कि अपोजीशन ने भी उसकी तारीफ की हैं। 70 लाख रूपया रख दिया है पचास लाख की कारपोरेशन बनेगी और फिर 20 लाख रूपया हरिजन कल्याण फंड का जो कांग्रेस सरकार ने नहीं दिया। इसी सरकार ने दिया है और इसके अलावा 26/27 लाख रूपया पलेनड बजट में रखा है। श्री राम किशन जी ने कहा कि सफाई मजदूर के लिये कुद नहीं किया। वह इस वक्त यहां हैं नहीं मै। उनको बताना चाहता हूं कि यह भी हरिजनों और हिन्दोस्तान के दूसरे पिछड़े समाज का अंग है और हरिजनों के लिये जो एक करोड़ से ज्यादा रकम रखी गई है उसमें से यह कैसे समझते है कि उन पर खर्च नहीं होगा? जरूर होगा यकीन रखें। दूसरे किसान हैं जो खेती करते हैं। उनके लिये जैसा कि मैं पहले भी कह चुका हूं इस बजट का 80 फीसदी रखा गया है। तीसरी किसम है शहरी लोगों की जो दुकानदारी करते हैं बिजनैस करते हैं। उनके बारे में अर्ज करता

हूं कि जो लोअर मिडल क्लास के हैं जो प्रोफैशनल टैक्स देते हैं उनके बारे में कांग्रेस सरकार ग्रास–इनकम पर प्रोफैशनल टैक्स लगाती थी लेकिन हमने ऐलान किया है कि यह टैक्स ग्रास इनकम पर न लगाकर नैट इनकम पर ही लगेगा। यह तो अंधेरे की बात थी कि ग्रास इनकम पर टैक्स लगे। अब रहा प्रापर्टी टैक्स का सवाल तो उसके बारे में मैं मानता हूं कि शहर में जो लोअर मिडल तबका रहता है उसके पास एक ही मकान आमतौर पर होता है जिसमें वह रहता है। इसके बारे मैं कांग्रेस सरकार ने यह कानून बनाया कि उस रिहायशी मकान को रेंटल वैल्यू के पहले तीन सौ रूपये तो माफ कर दिये और उससे ऊपर की आमदनी पर टैक्स लगा दिया आखिर जिसके पास एक ही रिहायर्श, मकान है उसके ऊपर इतना टैक्स क्यों हो आप भी मानेंगे कि यह शहरी और देहातों के बीच तमीज की बात है जो मुनासिब नहीं कि देहात में अगर किसी के पास छः मकान हों तो उन पर कोई टैक्स नहीं लगता लेकिन शहर में एक मकान पर भी जो उसका रिहायशी है टैक्स लगता है। सरकार इस बात को बड़ी सोरियसलो सोच रही है कि जो भाई एक ही मकान का मालिक है और जिसमें वह खुद रहता है उसको सालाना रेटल वैल्यू सारो की सारी माफ कर दे या यह तीन सौ वाली सलैब बड़ा कर सात आठ सौ कर दें। मैं इस वक्त कोई वायदा नहीं करता लेकिन यह सरकार इस बारे में सोचेंगी कि क्या होना चाहिए और अगर फिनाशल इम्पलीकेशनज ज्यादा न हुई तो शहरों में जो कोई अपनी मकान में रहता है उसको प्रापर्टी टैक्स पूरा माफ कर दिया जाएगा। इसके बाद

स्पीकर साहिब हमारा फोर्थ सैक्शन है इनडस्ट्रियलिस्ट का। मुझे इस बात का बहुत ताज्जुब हुआ कि हमारे किसी भाई ने भी हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने जो अभी हाल ही में इनडस्ट्रियलिस्टस की कानफ्रेंस बुलाई थी, उसका जिकर नहीं किया। यह कितनी खुशी की बात है कि हरियाणा के इनडस्ट्रियलिस्ट्स ने हरियाणा का नाम बम्ब्ई, कलकत्ता, और मद्रास आदि में बड़ा भारी ऊंचा किया है। हमउ न पर नाज कर सकते हैं। हमारे चीफ मिनिस्टर साहिब ने यह हिम्मत की कि उन्हे बुलाया और उनसे कहा कि आइए, हरियाणा अभी बना है यहां आकर इनडस्ट्रीज लगाइए। स्पीकर साहिब, उन हरियाणा के सपूतों ने जिन्होंने कि हरियाणा कानाम दूसरी स्टेटों में पैदा किया है इस बात को बहुत खुशी जाहिर की कि हरियाणा स्टेट बनने के बाद उन्हें दावत दी गई और इन्डस्ट्रोज लगाने के लिये कहा गया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हो रही है इस बात को कहने में कि इस कानफ्रेंस के नतीजे के तौर पर अब तक हमारे पास 25 करोड़ रूपये आ गई है। इस, तरीके से मुझे विश्वास है कि हरियाणा आगे बढ़ेगा और इस डायरैक्शन में तरक्की करेगा।

पांचवां सैक्शन, स्पीकर साहिब हमारा सरकारी कर्मचारियों का है। इनको मैंने अर्ज किया हमने सैन्टर गवर्नमेंट के रेट्स के मुताबिक महंगाई भत्ता दिया है और जो आधे के बारे में सरकारी कर्मचारियों को कहा गया है कि वे सी.टी.डी. या जी.पी. फंड मं जमा करें उसके बारे में भी मैंने जिक्र किया। तो इस तरह

से जितने भी हमारे सैक्शन्ज है हमने हरेक का ख्याल रखा है और हर सैक्शन के फायदे के लिये कोई न कोई बात रखी है।

आखिर में स्पीकर साहिब मैं यह कहना चाहता हूं कि हो सकता है कि बहुत से मेरे लायक दोस्तों ने जो सजैशन्ज दी हैं मै। उसके जवाब इस स्पीच में न दे सका हूं परन्तु मैं उन्हें विश्वास दिलाता हूं कि क्योंकि हमारे पास उसके नोट्स हैं, इसलिये सरकार जन पर विचार करेगी और जो जो बातें हरियाणा के इंट्रस्ट में होगी उनको लाजमी तौर पर इकबाल किया जाएगा।

इसके साथ ही साथ स्पीकर साहिब मैं एक बात और आपके द्वारा इस सदन से अर्ज करना चाहता हूं। कई लोग ऐसे हैं, हरियाणा में भी होंगे और हरियाणा से बाहर भी हैं, जो समझते हैं कि हरियसाणा एक छोटा सा राज्य है। इसकी 76 लाख की आबादी है और रक्बा 17–18 हजार मुरब्बा मील है। लकिन स्पीकर साहिब क्यों हमारे सदन के भाई बहन यह हरियाणा के भाई बहन इस छोटी सी बात पर परेशान होते हैं। आखिर इजराइल का नक्शा हमारे सामने हैं इजराईल की आबादी हमारी आबादी के 1/3 हिस्से से भी कम है और उसका रकबा आधे से कम है। अगर वह पिछले 10–15 सालों में इतनी तरक्की कर सकात है तो हरियाणा के लोग भी तरक्की कर सकते हैं। हरियाणा के लोगों में भी जजबा है, हिम्मत है, इनटैलिजैंस है और यहां के लोग बहादुर हैं। स्पीकर साहिब आपको जान कर खुशी हुई होगी कि इस साल भी मैट्रिक में पंजाब युनिवर्सिटी की परीक्षा

में जो फर्स्ट आए हैं वे हरियाणा के ही स्टुडैन्टस हैं (तालियां) हरियाणा के किसान का हिम्मत मैं कोई मुकाबला नहीं कर सकता। सात्विक वृति में हिन्दुस्तान का कोई हिस्सा हरियाणा का मुकाबला नहीं कर सकात (तालियां) अगर यहां कोई कमी रही है वह यह कि हमारी किस्मत की बागडोर हमारे हाथों में नहीं थी। आज हमें खुशी है कि हमारी किस्मत की बागडोर हमारे हाथों में है और उन लोगों के हाथों में है जिन्होंने हरियाणा की लड़ाई लड़ी, जिन्होंने लड़ाई लड़ती दफा मुसीबत की कोई परवाह नहीं की। आज मुझे इस सदन को बताते बड़ी भारी खुशी है कि जिन उमंगों को लेकर हमने हरियाणा की लड़ाई लड़ी थी उन्हीं उमंगों को लेकर हम हरियाणा की सेवा करना चाहते हैं और कर रहे हैं और मैं प्रार्थना करता हूं कि ज्यादा नहीं तो कम से कम दो साल हमें काम करने का चान्स दीजिए टांग घसीटने की बात मत कीजिए। यदि ऐससा हुआ तो मैं यकीन दिलाता हूं हम दो वर्ष में ही उतना काम कर के बता देगें जितना कांग्रेस 20 सालों में नहीं कर सकी। (जोर से तालियां बजीं) इन शब्दों के साथ में आपका अध्यक्ष महोदय शुक्रिया आद करता हुआ इस बजट की ताईद करता हूं।

चौधरी रिजक रामः स्पीकर साहिब, आज कल के हालात में जबकि इजरायल के मुताल्लिक सिक्योरिटी कौंसिल आदि में बातचीत चल रही हो, इस तरह के कमैन्डेबल शब्द कहना शायद मुनासिब नहीं है।

वित मंत्रीः मैंने स्पीकर साहिब जो कुछ कहा है वह फुल रिसपौंसिबिलिटी से कहा है।

श्री अध्यक्षः किसी की तारीफ करने में कोई बुराई नहीं। अगर बुराई करते तो और बात थी।

The House stands adjourned till 2.00 P.M. on 19th June, 1967.

11.45 A.M.

(The Sabha then adjourned till 2.00 P.M. on Monday, the 19th June, 1967).